स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–23, अंक–9
श्रावण–भाद्रपद 2072, सितंबर 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **34-37**

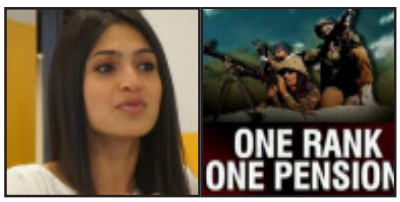

कवर तृतीय पेज **39**
कवर चतुर्थ पेज **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–6

चीन का संकट, भारत के लिए अवसर

डॉ. अश्वनी महाजन

1 कवर पेज
2 कवर द्वितीय पेज

09 पर्यावरण विशेष
ग्लोबल वार्मिंगः भारत पर संकट का दस्तक
..... **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

11 पर्यावरण विशेष–2
पानी चाहिए तो हिमालय बचाना होगा
..... **सुरेश नौटियाल**

14 पर्यावरण विशेष–3
शास्त्रों में है पर्यावरण रक्षा के बेहतर उपाय
..... **श्रीश देवपुजारी**

17 जीएम फसलें
मक्के की रोटी और सरसों का साग जुमला रह जायेगा
..... **डॉ. देवेन्द्र शर्मा**

19 मुद्दा
प्याज पर हाहाकार, खामोश सरकार!
..... **डॉ. वेदप्रताप वैदिक**

20 उद्योग
भारतीय हथकरघा उद्योग – ब्रांड के साथ बाजार में उतरने की तैयारी
..... **जैकब अब्राह्म**

22 रिपोर्ट
गीता प्रेस पर संकट मजबूरी या षडयंत्र
..... **स्वदेशी संवाद**

24 इतिहास
बंदेमातरम् क्रांति का देव मंत्रा
..... **सरोज मित्र**

26 जयंती
25 सितंबर श्री दीनदयाल जयंती के विशेष उपलक्ष्य में
..... **डॉ. विजय वशिष्ठ**

28 चिंतन
गरीबों की बदहाली का जिम्मेदार कौन?
..... **निरंकार सिंह**

30 शिक्षा
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस – 8 सितंबर पर विशेष
..... **अरूण तिवारी**

पाठकनामा

आरक्षण आर्थिक विपन्नता के आधार पर क्यों नहीं?

जातिगत आरक्षण के बजाए क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होनी चाहिए? जब देश में आरक्षण लागू किया गया तो उस समय उसका मूल उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर जातियों, उपजातियों या खास वर्गों को सहायता प्रदान करना। किन्तु धीरे–धीरे राजनेताओं ने वोट बैंक के चलते अपेक्षाकृत मजबूत जातियों या वर्गों को भी आरक्षण व्यवस्था में शामिल करा दिया। चाहे उस जाति या वर्ग के लोग आर्थिक रूप से संपन्न ही क्यों न हो।

मनोज कुलियाल, *नई दिल्ली*

*****

बिहार के पैकेज की निगरानी जरूरी

प्रधानमंत्री ने बिहार को सवा लाख करोड़ का पैकेज देकर नई पीढ़ी के लिए विकास के सपने जगा दिए है। जिस सपने को पिछले तीन दशक से लगातार रौंदा जा रहा है। इतनी बड़ी राशि खर्च कैसे हो और उसके लिए उत्तरदायित्व किसे बनाया जाए, यह तय करना जरूरी है। नितीश कुमार, लालू प्रसाद यादव से मिलकर भ्रष्टाचार के मामलों में समझौता कर चुके हैं। लूट–खसूट की राजनीति बिहार में अब बंद होनी चाहिए। भाजपा सरकार ही वहां एक अच्छा विकल्प है।

उज्ज्वल, *छपरा, बिहार*

*****

कुछ मनोरंजक भी हो जाए

स्वदेशी पत्रिका में लगातार आर्थिक एवं वैश्विक विषयों पर लेख पढ़ने को मिलते रहे हैं। इससे ज्ञान बढ़ता है और सरकार एवं शासन के बारे में हम सजग होते हैं। लेकिन पत्रिका में मनोरंजन, खेल, संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित सामग्री कम ही देखने को मिलती है। यदि इन विषयों को शामिल कर दिया जाए तो यह पत्रिका पूर्णतया पारिवारिक हो सकती है। पत्रिका में हर वर्ग एवं हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ सामग्री हो।

उज्ज्वल, *छपरा, बिहार*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

लोहिया ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनके चेलों ने उसी कांग्रेस से सत्ता के लिए हाथ मिला लिया

नरेन्द्र मोदी
(भागलपुर में)

वैश्विकरण के इस दौर में हम जिस दुनिया में रहते है उसमें हमारा अस्तित्व एक–दूसरे के भविष्य पर ही निर्भर है।

लि केकियांग
चीनी प्रधानमंत्री

ब्याज दर में कटौती का यह सबसे उपयुक्त अवसर है।

अरविन्द पनगरिया
नीति आयोग के उपाध्यक्ष

एक विकसित अर्थव्यवस्था वह नहीं है जिसमें एक गरीब भी कार खरीद सकता है बल्कि वह है जिसमें एक अमीर भी सार्वजनिक वाहन से चल सकता है।

अजीत राणाडे
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री

संपादकीय

बिडंबनाओं की नीतियां

सरकार ने न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की प्रत्यक्ष कर मामलों के संबंध में एक अप्रैल 2015 से पहले की अवधि के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों व विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों पर बकाया न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट (एमएटी) की सिफारिशें मानते हुए 64 हजार करोड़ की राशि को वसूलने का इरादा छोड़ दिया है। यही नहीं यह भी तय किया गया है कि आयकर अधिनियम में उचित संशोधन किया जाएगा और एक अप्रैल 2015 से पूर्व विदेशी निवेशकों पर मैट का प्रावधान लागू ही नहीं माना जाएगा। वित्त मंत्रालय ने सभी फील्ड अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है कि विदेशी निवेशकों के मामलों से संबद्ध लंबित मूल्यांकन कार्यवाही को स्थगित रखा जाये। अगर कोई बकाया मांग है भी तो उसकी वसूली न की जाए। सरकार की दलील है कि मैट के कारण विदेशी निवेशकों के मन में भय था और उसको दूर करना जरूरी था। वित्तमंत्री अरूण जेटली का यह भी तर्क है कि पूरी दुनिया पर जिस तरह मंदी का साया मंडरा रहा है उसे देखते हुए यह जरूरी है कि विदेशी निवेशकों को भारत के प्रति आकर्षित करने के लिए उचित माहौल बनाया जाए। हालांकि एक तरफ सरकार यह कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत धरातल पर खड़ी है और यहां आकर भारी निवेश करने वालों की लाइन लगी है, दूसरी तरफ यह भी आशंका है कि कहीं विदेशी निवेशक नाराज न हो जाए। हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की मुंबई में हुई बैठक में भी दोहराया गया कि हमारा वृहद आर्थिक आधार काफी मजबूत है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के कारण चिंता की तत्काल कोई वजह नहीं है। इसके बावजूद चौकसी बरतने और स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि नीतियों में एक तरफ विदेशी निवेशकों की नाराजगी और उनकी शिकायतों का विशेष महत्व मिल रहा हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की आत्महत्या और भुखमरी रोकने के लिए जो किया जा रहा है वह न सिर्फ अपर्याप्त है बल्कि बहुत देरी होने के कारण लगातार जान देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। कहने को तो मॉनसून देरी से आने और इसकी अनिश्चितता के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। खड़ी कृषि फसलों और बहुवर्षीय बागवानी को बचाने के लिए तुरंत उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जिसमें 100 करोड़ रुपये के आवंटन से फसलों की रक्षात्मक सिंचाई के लिए डीजल अनुदान सहायता योजना, फसलों की दोबारा बुआई के लिए किसानों को अतिरिक्त बीज सब्सिडी, डेढ़ सौ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन से बहुवर्षीय बागवानी फसलों की सुरक्षा, और मवेशियों के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन अभी हाल में लिए फैसले हैं। परंतु सूखे की भयावहता और किसानों की दयनीयता की समीक्षा के लिए भी कोई आयोग या एक्शन ग्रुप भी नहीं बनाया गया। जिस मात्रा और जितनी त्वरित सहायता किसानों को चाहिए, क्या उसका कोई आकलन किया गया है, संभवतः नहीं। यदि ऐसा होता तो किसान सिर्फ एक लाख की मुआवजे के लिए आत्महत्या नहीं करते। हर साल महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सूखे पड़ते हैं और कुछ दिनों की चिल–पौ के बाद सब भुला दिया जाता है। जरूरत है कि अब इन मुद्दों को भी उतनी ही प्राथमिकताएं दी जाएं, जितनी कि हम विदेशी निवेशकों से जुड़े एवं अन्य मुद्दों को देते आ रहे हैं।

चीन का संकट, भारत के लिए अवसर

हाल ही में चीन द्वारा अपनी करैंसी के 4.4 प्रतिशत से भी ज्यादा अवमूल्यन करने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों और विदेशी मुद्रा बाजारों में भारी खलबली मच गई है। युआन के अवमूल्यन की प्रतिस्पर्द्धा में दुनिया भर की करैंसियों में डालर के मुकाबले भारी अवमूल्यन हुआ, ताकि युआन के अवमूल्यन का उनपर कोई असर न हो। इतिहास गवाह है कि मुद्रा के प्रतिस्पर्द्धी अवमूल्यन का कभी किसी देश को लाभ नहीं हुआ है। 1930 के दशक की वैश्विक मंदी के दौरान भी इसी प्रतिस्पर्द्धी अवमूल्यन ने अर्थव्यवस्थाओं को चौपट किया था। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार यदि सभी देश अपनी–अपनी करैंसी का अवमूल्यन करते हैं, तो किसी भी देश को उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन इस उथल–पुथल का खामियाजा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा।

अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार यदि सभी देश अपनी–अपनी करैंसी का अवमूल्यन करते हैं, तो किसी भी देश को उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन इस उथल–पुथल का खामियाजा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। –
डॉ. अश्वनी महाजन

प्रधानमंत्री का कमर कसने का आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंदी की आशंका के मद्देनजर भारतीय उद्योगपतियों को कमर कसने का मंत्र दिया है। अपने आवास पर शीर्ष मुख्य कार्यकारियों, बैंकरों, अर्थशास्त्रियों और मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी भारत के लिए कई तरह के अवसरों के द्वार खोल सकती है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में भारी मंदी, युआन के हाल के अवमूल्यन और अमेरिका में ब्याज दरे में बढ़ोतरी की संभावना से जुड़ी चिंता से वैश्विक बाजार में उठा–पटक का माहौल है। बैठक का विषय था– हाल का वैश्विक घटनाक्रम : भारत के लिए अवसर। प्रधानमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन के अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, बिजली मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से तेज विकास की पटरी पर लाया जाए, इस विचार विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग से कहा कि वे जोखिम लें और निवेश करें। ❑

क्यों करना पड़ा युआन का अवमूल्यन

पिछले कुछ समय से चीन की अर्थव्यवस्था भारी संकटों से गुजर रही है। यह सर्वविदित ही है कि पिछले दो से ज्यादा दशकों में चीनी अर्थव्यवस्था में तेजी से ग्रोथ हो रही थी, जो कई बार 15 प्रतिशत से भी ज्यादा पहुंच गई। मोबाईल फोन और अन्य टेलीकॉम उपकरणों, खिलौनों, बिजली के साजो–समान, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं से लेकर बड़ी और छोटी मशीनों सभी प्रकार की वस्तुओं का चीन भारी मात्रा में निर्यात करने लगा और भारत ही नहीं, अमरीका और यूरोप के मुल्कों के बाजारों में चीनी माल का आधिपत्य हो गया। चीन में चीनी कम्पनियां ही नहीं अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी वहां जाकर उत्पादन करने लगी। भारत से भी बड़ी मात्रा में उद्योगपतियों ने पलायन कर चीन में जाकर अड्डा जमा लिया और चीन दुनिया का 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बन गया।

अब तक चीन युआन में ४.४ प्रतिशत तक अवमूल्यन कर चुका है।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन संकटों में आ गया है। उसका पहला संकट है, वहां भारी मुद्रा स्फीति। चीन में कीमतें बढ़ने लगी थी, जिसके कारण अब मजदूरी दर भी बढ़ गई थी। सामान्य मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 960 युआन प्रतिमाह से बढ़कर 2015 में 1820 युआन तक पहुंच गई। दूसरे, चीन की प्रांतीय सरकारें जो चीनी उत्पाद को सस्ता रखने के लिए सब्सिडी देती थी, उसके कारण चीन में राजकोषीय घाटा सीमाएं पार कर चुका था। अब सब्सिड़ी देने की स्थिति में नहीं रही। गौरतलब है कि चीन का आंतरिक ऋण 2008 में जीडीपी के 125 प्रतिशत से बढ़ता हुआ जून 2015 तक 207 प्रतिशत तक पहुंच चुका है (ब्लूमबर्ग बिजनेस)। इसके बाद निर्यातों को सस्ता रख अपनी प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखना, चीन के लिए संभव नहीं था। तीसरे, अमरीका और यूरोप में आई मंदी के चलते चीन से इन देशों को निर्यात घटने लगे और यही नहीं चीनी माल के पहले से महंगा होने के कारण अब दूसरे मुल्कों ने भी अमरीका, यूरोप और अन्य देशों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। चीन की मंदी का चौथा महत्वपूर्ण कारण था, वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश का घटना। चीन ने पिछले दो दशकों के दौरान रेल, सड़क, बिजली समेत तमाम प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है, लेकिन अब उस निवेश की गति बहुत धीमी हो गई, जिसके चलते चीन में ग्रोथ घटने लगी।

दो दशकों से अधिक समय तक लगातार भारी ग्रोथ करने के बाद चीन ग्रोथ में आई इस मंदी को सह नहीं पा रहा है। उसके शेयर बाजारों ने अब नीचे का रूख अख्तियार कर लिया और अभी तक पिछले कुछ महीनों में चीनी शेयर बाजार 40 प्रतिशत तक घट चुके हैं। निवेशक जो पहले चीन के शेयर बाजारों में निवेश कर रहे थे, अब वापिस होने लगे। ऐसे में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार भी अब कम होने लगे। अपने निर्यातों को बढ़ाने की कवायद में और देश से विदेशी निवेशकों को बाहर जाने से हतोत्साहित करने के लिए चीनी सरकार ने युआन का अवमूल्यन करने का निर्णय किया और पिछले 10 अगस्त को उसने युआन में 2 प्रतिशत का अवमूल्यन किया, उसके बाद कई दिनों तक अवमूल्यन करने का क्रम जारी रहा और अब तक चीन युआन में 4.4 प्रतिशत तक अवमूल्यन कर चुका है।

भारत पर भी पड़ा असर

24 अगस्त 2014 को मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक (सेनसेक्स) ने 1624 अंकों का गोता लगाया, यह एक ऐतिहासिक गिरावट थी। बर्षों बाद ऐसा हुआ है। रूपया भी निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के हालात गंभीर है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में आये संकट से जरा भी घबराने वाली स्थिति नहीं है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि शेयर बाजार यानि सेंसेक्स कभी भी इकोनॉमी की सेहत को दर्शाने का एकमात्र मापदंड नहीं है।

अल्पकालिक है असर

भारतीय परिदृश्य में देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। सोना और कच्चे तेल के दामों में गिरावट बनी हुई है। मुद्रास्फीति की दर भी

थोक और खुदरा बाजार में नियंत्रण में है। सबसे अहम बात है कि राजनीतिक स्थिरता के साथ लोगों में उत्साह बरकरार है। साथ ही चीन के साथ भारतीय बाजारों के बहुत अधिक अंतर्संबंध नहीं है जैसे कि हमारे अमरीका के साथ हैं। इसलिए अमरीका में वर्ष 2007–08 में आए आर्थिक संकट का असर हमें भी झेलना पड़ा था। गौरतलब है कि चीन का भारत में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं है।

चीन के संकट से भारत के लिए अवसर

अभी हालात ये हैं कि चीन ने 'मास प्रोडक्शन' के अपने फॉर्मूले के जरिए भारत को अपना माल खपाने के बाजार के रूप में तलाशा है। चीन की अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट के जरिए हम अपने उद्योगों को और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के पास उद्यमियों के लिए निवेश और उत्पादन अनुकूल वातावरण देने का वादा भी है। साथ ही हमारी सरकार की ओर से निवेशकों को 'मेक इन इंडिया' के जरिए निवेश का आमंत्रण भी दिया जा रहा है। आज हम मंगल ग्रह की कक्षा तक अपने उपग्रह को भेज सकते हैं, वह भी बहुत कम लागत में, दूरस्थ मार करने वाले मिसाईल ही नहीं, परम कम्प्यूटर और एटम बम तक बना सकते हैं, तो उद्योगों के विकास में क्या कठिनाई है। संकेत स्पष्ट है कि हम बाजार की उठापटक को भी अपने लिए अवसरों में तबदील कर सकते हैं। ❑❑

चीन भी निवेशकों को लुभाने में जुटा

चीन ने दुनियाभर के निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए हर स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। आर्थिक सुधारों के ऐलानों के साथ चीन के प्रधानमंत्री खुद डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आ गए हैं। उत्तर पूर्व चीन में दावोस बैठक के उद्घाटन के अवसर पर ली केकियांग ने साफ कहा कि चीन की इकोनॉमी कुछ सुस्त हुई है लेकिन ये अभी भी काफी मजबूत है।

प्रधानमंत्री केकियांग के मुताबिक फिलहाल चीन की अर्थव्यवस्था कुछ मुश्किलों से गुजर रही है, लेकिन अभी भी चीन में चुनौतियों से कहीं ज्यादा अवसर मौजूद है। हालांकि उन्होने माना कि पहले छह महीनों में 7 फीसदी ग्रोथ का लक्ष्य हासिल करना आसान काम नहीं था। केकियांग ने कहा कि 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में 7 फीसदी की ग्रोथ पहले की 10 फीसदी की ग्रोथ से ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उस वक्त के मुकाबले अर्थव्यवस्था काफी बढ़ चुकी है। उनके मुताबिक नई औद्योगिक नीति, आईटी, शहरी करण और खेती के उन्नत तरीकों की वजह की मदद से जल्द इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिलेगी।

ली केकियांग ने उन सभी आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि युआन के डीवैल्युएशन से करेंसी वार शुरू हो सकता है। अपने संबोधन में केकियांग ने कहा कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि करेंसी वार शुरू हो। उनके मुताबिक चीन के पास अपनी अर्थव्यवस्था को एक सीमा में रखने को पूरी क्षमता है, और फिलहाल अर्थव्यवस्था कंफर्ट जोन में ही है। चीन फिलहाल दो संकेटों से जूझ रहा है, इसमें स्टॉक मार्केट क्रैश और स्लोडाउन शामिल हैं। चीन का स्टॉक मार्केट जून के अपने उच्चतम स्तर से 40 फीसदी टूट चुका है। चीन फिलहाल स्टॉक मार्केट को संभालने के लिए 236 अरब डॉलर के राहत पैकेज दे चुका है। वहीं हाल में ही आए एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा से भी चीन में सुस्ती के संकेत मिले हैं। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

ग्लोबल वार्मिंगः भारत पर संकट का दस्तक

प्रशांत महासागर के द्विपीय राज्यों के प्रमुखों से वार्ता करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रति भारत की गंभीरता का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय एवं अंटार्टिका में जमे हुये ग्लेश्यिर के पिघलने का अनुमान है। इस पानी के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा ओर कई द्वीप जलमग्न हो सकते हैं। मोदी की आगामी अमरीकी यात्रा में भी ग्लोबल वार्मिंग पर अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा से चर्चा हो सकती है। मोदी के इन प्रयासों के लिये साधुवाद। लेकिन इससे अधिक जरूरत ग्लोबल वार्मिंग का अपने देश की कृषि और देश के किसानों पर पड़ने वाला प्रभाव है।

पिछले 100 वर्षों में भारत में तापमान 0.6 डिग्री बढ़ा है। अनुमान है कि इस सदी के अन्त तक इसमें 2.4 डिग्री की वृद्धि होगी जो कि पिछली सदी में हुई वृद्धि का चार गुणा है। दुनिया के तमाम देशों द्वारा स्थापित इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन कलाइमेट चेंज ने अनुमान लगाया है कि बाढ़, चक्रवात तथा सूखे की घटनाओं में भारी वृद्धि होगी। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जो भीषण बाढ़ अब तक 100 वर्षों में एक बार आती थी वैसी बाढ़ हर दस वर्षों में आने की संभावना है। पूरे वर्ष में होने वाली वर्षा लगभग पूर्ववत रहेगी परन्तु इसका वितरण बदल जाएगा। जोरदार बारिश के बाद लम्बा सूखा पड़ सकता है।

पिछली सदी में हुई तापमान में मामूली वृद्धि से हजारों किसान आत्महत्या को मजबूर हुए है। अनुमान लगाया जा सकता है कि चार गुणा वृद्धि से कितनी तबाही मचेगी। यह दुष्प्रभाव असिंचित खेती पर ज्यादा पड़ेगा। देश के बड़े इलाके में बाजरा, मक्का तथा रागी की खेती होती है जो कि पूर्णयता वर्षा पर निर्भर रहती है। वर्षा का स्वरूप बदलने से ये फसलें चौपट होगी। किसानों की मांग होगी कि सिंचाई का विस्तार हो। जाड़े में होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए विशेषकर उपयोगी होती है। इस वर्षा में भी कमी होने का अनुमान है। फलस्वरूप वर्तमान में सिंचित क्षेत्रों में भी सिंचाई की मांग बढ़ेगी। लेकिन पानी की उपलब्धता घटेगी। अनुमान है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ने वाली बर्फ की मात्रा कम होगी। गर्मी के मौसम में यह बर्फ ही पिघल कर हमारी नदियों में पानी बनकर बहती है। बर्फ कम गिरने से गरमी में नदियों में पानी की मात्रा कम होगी। इसके अतिरिक्त हमारे भूमिगत जल के तालाब भी सूख रहे है। लगभग पूरे देश में ट्यूबवेल की गहराई बढ़ाई जा रही है चूँकि भूमिगत जल का अतिदोहन हो रहा है। जितना पानी वर्षा के समय भूमि में समाता है उससे ज्यादा

पिछली सदी में हुई तापमान में मामूली वद्धि से हजारों किसान आत्महत्या को मजबूर हुए है। अनुमान लगाया जा सकता है कि चार गुणा वद्धि से कितनी तबाही मचेगी।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

निकाला जा रहा है। भूमिगत जल का पुनर्भरण कम हो रहा है चूँकि बाढ़ पर नियंत्रण करने से पानी फैल नही रहा है और भूमि में रिस नही रहा है।

सरकार की नीति है कि वर्षा के जल को टिहरी तथा भाखड़ा जैसे बड़े बांधों में जमाकर लिया जाए। बढ़ते तापमान के सामने यह रणनीति भी फेल होगी चूँकि इन तालाबों से बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होगा जिससे पानी की उपलब्धता घटेगी। अमरीका के 12 बड़े तालाबों के अध्ययन में अनुमान लगाया है कि वाष्पीकरण में नौ प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह ठंडे देश की बात है। भारत जैसे गरम देश में वाष्पीकरण से पानी का घाटा ज्यादा होगा। हम हर तरफ से घिरते जा रहे हैं। सिंचाई की मांग बढ़ेगी परंतु पानी की उपलब्धता घटेगी। बर्फ कम गिरने से गर्मी में नदी में पानी कम होगा। बाढ़ पर नियंत्रण करने से भूमिगत जल का पुनर्भरण नही होगा। बड़े बांधों से वाष्पीकरण होने से पानी की हानि ज्यादा होगी।

एक और संकट सामरिक है। मसेचूसेट्स इन्सटीट्यूट आफ टेकनालोजी द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के देशों की कृषि के लिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सकारात्मक होगा। वर्तमान में यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। तापमान में कुछ वृद्धि से इन देशों का मौसम कृषि के अनुकूल हो जाएगा। अतः विकसित देशों का पलड़ा भारी हो जाएगा। उनके यहाँ खाद्यान उत्पादन बढ़ेगा जबकि हमारे यहाँ घटेगा। साठ के दशक में हमें अमरीका से खाद्यान की भीख मांगनी पड़ी थी। वैसी ही स्थिति पुनः उत्पन्न हो सकती है।

इस उभरते संकट का सामना करने के लिए हमें अपनी कृषि और जलनीति में मौलिक परिवर्तन करने होंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमने खाद्यान्नों की अपनी पारंपरिक प्रजातियों को त्याग

जरूरी है कि हम खाद्यान्नों की पारंपरिक प्रजातियों को अपनाएं। ये पानी कम मांगती है।

कर हाई इल्डिंग प्रजातियों को अपनाया है। इससे खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा है। परंतु ये प्रजातियाँ पानी के संकट को बर्दाश्त नही कर पाती हैं। पर्याप्त पानी न मिलने पर इनका उत्पादन शून्य प्राय हो जाता है। तुलना में हमारी पारंपरिक प्रजातियाँ मौसम की मार को झेल लेती है, यद्यपि उत्पादन कम होता है। अपनी खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम खाद्यान्नों की पारंपरिक प्रजातियों को अपनाएं। ये पानी कम मांगती है। प्रश्न है कि इनकी खेती से आई उत्पादन में गिरावट की भरपाई कैसे होगी? उपाय है कि अंगूर, लाल मिर्च, मेन्था और गन्ने जैसी जल–सघन फसलों पर टैक्स लगाकर इनका उत्पादन कम किया जाए अथवा केरल जैसे प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में इनकी खेती को सीमित कर दिया जाए। इन उत्पादों का आयात भी किया जा सकता है। इन फसलों का उत्पादन कम करने से पानी की बचत होगी। इस पानी का उपयोग पारंपरिक प्रजातियों से खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। तब हमारी खाद्य सुरक्षा स्थापित हो सकेगी। तूफान, सूखा तथा बाढ़ के समय हमारे किसानों को कुछ उत्पादन मिल जाएगा और वे आत्महत्या को मजबूर नही होंगे। हाँ अंगूर जैसी विलासिता की वस्तुएँ बहुत मंहगी हो जाऐगी। खाद्यान्न भी कुछ मंहगे होंगे, चूँकि प्रति हेक्टेयर उपज कम होगी, जबकि लागत लगभग पूर्ववत रहेगी। अपनी खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें खाद्यान्नों की इस छोटी मूल्य वृद्धि को स्वीकार करना चाहिए।

दूसरा विषय जल संसाधनों का है। मानसून के पानी का भंडारण जरूरी है, परन्तु बड़े बांधों में भंडारण करना हानिप्रद है चूँकि इनसे वाष्पीकरण अधिक होता है। उपाय है कि वर्षा के जल का भंडारण भूमिगत जलभृत में किया जाए। धरती के गर्भ में विशाल तालाब होते हैं जिन्हें जलभृत कहा जाता है। वर्षा के पानी को ट्यूबवेलों के माध्यम से इन जलभृतों में डाला जा सकता है। नदियों द्वारा पहाड़ से लाए जा रहे पानी को भी मोड़कर इन ट्यूबवेलों में डाला जा सकता है। जलभृत में पड़े पानी का वाष्पीकरण नही होता है। विशेष यह कि देश भर में बाढ़ के नियंत्रण के लिए नदी किनारों पर बने सभी तटबंधों को तोड़ देना चाहिए। बाढ़ के पानी को फैलने देना चाहिए जिससे जलभृत का पुनर्भरण हो। गाँव ऊँचे स्थानों पर तथा मकानों को स्टिलट पर बनाना चाहिए। जिससे बाढ़ से जानमाल का नुकसान न हो। यह खुशी की बात है कि मोदीजी ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक हैं। परन्तु दूसरे देशों के साथ इस मुद्दे पर कोरे भाषण देने से काम नहीं चलेगा। जरूरत है कि देश की कृषि पर मंडराते संकट से निबटने की रणनीति बनाई जाये। अपना घर जल रहा हो तो पड़ोसियों के साथ अग्निशमन पॉलिसी पर वार्ता बेमतलब होती है। पहले घर में लगी आग बुझाना चाहिये। ❑❑

bharatjj@gmail.com

पानी चाहिए तो हिमालय बचाना होगा

हिमालय के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से वर्षा के पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है और जो हिमनद बचे हैं, उनके समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
– सुरेश नौटियाल

अलवर, राजस्थान स्थित तरुण भारत संघ ने वर्ष 2007 में एक पुस्तक छापी थी– भारतीय जल दर्शन। इसके एक अध्याय– प्रलयकाल में जल का वर्णन– में पुराणों के हवाले से कहा गया है कि प्रलय का समय आने तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। किसी को अन्न नहीं मिलता, ब्रह्माण्ड गोबर के उपले की तरह धू–धूकर जलने लगता है... सब कुछ समाप्त हो जाता है... इसके बाद सैकडों वर्षों तक सांवर्तक वायु चलती है और इसके पश्चात असंख्य मेघ सैकडों वर्षों तक वर्षा करते हैं। सब कुछ जलमग्न हो जाता है...।

नहीं मालूम कि यह पौराणिक आख्यान कितना सच होगा पर आज इस सबकी अनुभूति सी होने लगी है। वर्षा का चक्र बिगड गया है, अन्न की कमी हो ही चुकी है और पृथ्वी उपले की तरह तो नहीं जल रही पर तापमान खूब बढ़ गया है और वैसा ही कुछ अहसास दे रही है।

जलवायु वैज्ञानिकों का एक वर्ग भी मानता है कि हर एक लाख वर्ष के बाद धरती 15–20 हजार वर्ष तक गर्म रहती है और वर्तमान जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया कोई 18 हजार वर्ष पहले शुरू हो गई थी। उनके अनुमान के अनुसार प्लेस्टोसीन हिमयुग के बाद यह प्रक्रिया आरंभ हुई होगी। इस युग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया हिम की अत्यन्त मोटी परतों से ढँके पडे थे।

यह भी अनुमान है कि करीब दो हजार साल बाद हिम युग की ओर लौटते समय खूब लम्बी वर्षा होगी और धरती अन्ततः एक लाख वर्ष के लिये हिमयुग में लौट जाएगी। कुल मिलाकर, इंटर–ग्लेशियल पीरियड कहा जाने वाला ज्यादा तापमान वाला यह वर्तमान काल मात्र 20 हजार वर्ष के आस–पास का होगा और करीब 18 हजार वर्ष इसे हो चुके हैं। इस धारणा में भी कितना दम है, नहीं मालूम।

बहरहाल, धरती के वातावरण और तापमान के बारे में फ्रांस के फिजिसिस्ट जोसेफ फूरी ने 1824 के आस–पास ग्रीनहाउस गैस के सिद्धान्त का पहली बार प्रतिपादन किया। 1896 में स्वीडिश रसायनशास्त्री स्वान्ते अरेनियस ने कहा कि औद्योगिक युग शुरू होने के साथ ही सीओ–टू उत्सर्जन से ग्रीनहाउस प्रभाव बढने लगा होगा। सम्भवतः यह भी किसी वैज्ञानिक ने पहली बार कहा कि मानव की गतिविधि से ग्रीनहाउस गैसें पैदा होती हैं।

बाद में 1938 में ब्रिटिश इंजीनियर गाई कैलेंडर ने जोडा कि जीवाश्म ईंधन जलने के कारण धरती का तापमान बढा है। ये बातें लंबे हिमयुग और छोटे तापयुग की थियरी से बहुत मेल नहीं खाती हैं, लेकिन ज्यादा तार्किक और वैज्ञानिक लगती हैं।

इस तार्किक और वैज्ञानिक धारणा को आगे बढाते हुए 1975 में अमेरिकी वैज्ञानिक

वैलेस ब्रोकर ने अपने एक शोधपत्र में 'ग्लोबल वार्मिंग' उपमा का उपयोग किया। इसके चार साल बाद 1979 में विश्व जलवायु सम्मलेन आयोजित हुआ। इस सम्मलेन ने विश्व सरकारों से आग्रह किया कि जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका को समझें और इस पर अंकुश लगाएँ।

इसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। मसलन, 1987 में मांट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया और 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने आईपीसीसी का गठन किया और 1990 में आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट सामने आई। 1992 में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मलेन हुआ और पाँच साल बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत औद्योगिक देशों से कहा गया कि 1990 के दशक में गैसों के उत्सर्जन का जो स्तर था, उससे भी पाँच फीसद कम उत्सर्जन का लक्ष्य वे 2008–2012 के बीच हासिल कर लें। अनेक देश इस लक्ष्य से सहमत नहीं थे। अमेरिका ने तो क्योटो प्रोटोकॉल से स्वयं को बाहर ही कर दिया था।

वर्ष 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल धरातल पर आया पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति में कोई सुधार नहीं है। विश्व की विवश जनता जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाले शिखर सम्मेलनों पर आस लगाए रहती है पर निकलता कुछ नहीं है। इस विषय पर पेरिस में कॉप–21 शिखर बैठक होने जा रही है पर अब तक दुनिया की सरकारों ने जो किया, उसे देखते हुए कॉप–21 से भी अधिक आशा करना मूर्खता ही होगा। लगता है कि गोलचक्कर काटकर हम बार–बार उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से यात्रा आरंभ करते हैं।

जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे आयाम हैं पर यहाँ पानी पर ही बात करेंगे और वह भी हिमालय के पानी पर। उस हिमालय के बारे में जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा

संकट इतना बढ़ गया है कि कोई नहीं जानता कि ये नदियाँ कब तक सदानीरा रहेंगी।

बर्फ अपने पास आज भी रखे हुए है।

जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है और हिमालय के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से वर्षा के पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है और जो हिमनद बचे हैं, उनके समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्थात, वर्षा कम होगी तो हिम कम बनेगा और जितना बनेगा भी उतना टिकेगा भी नहीं तापमान बढ़ने के कारण।

जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र के अलावा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा कही जाने वाली नदियों के बेसिनों में रहने वाली करोडों की आबादी प्रभावित हो रही है। संकट इतना बढ़ गया है कि कोई नहीं जानता कि ये नदियाँ कब तक सदानीरा रहेंगी। जिन 16 हजार से अधिक हिमालयी हिमनदों पर ये नदियाँ निर्भर हैं, वे स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आकर छोटा हो रहा है और उनमें जो हिम है उसकी सघनता में भारी कमी आ रही है।

आईपीसीसी की 2007 की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मानव गतिविधियों के कारण बढ़े तापमान के कारण भविष्य में इन नदियों में जलवायु परिवर्तन के कारण पानी का बहाव काफी कम हो जाएगा और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। एक और खतरे की घंटी है। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक जे. श्रीनिवासन तो पहले ही कह चुके हैं कि बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारत के अधिकतम हिस्सों के सतही वायु तापमान में आधा डिग्री की वृद्धि हुई, लेकिन हिमालय क्षेत्र में यह वृद्धि एक डिग्री सेंटीग्रेड की रही। इसी वजह से हिमनदों के पिघलने की गति तेज हुई।

हिमालयी कृषि पर तापमान बढ़ने का बुरा असर आज कोई भी देख सकता है। हिमालयी राज्यों में कृषि लगभग समाप्त होने का कारण केवल वन्य पशुओं का हस्तक्षेप नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन प्रमुख है।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट "हिमालयन ग्लेशियर्स" भले ही कहती हो कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी हिमनद प्रभावित हुए हैं। लेकिन, हिमनदों की टर्मिनस पोजीशन की नाप से पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र के हिमनद पिछले कुछ दशकों से निरंतर घट रहे हैं।

उदाहरण के लिये 1960 के दशक से लेकर अब तक सगरमाथा (एवरेस्ट) क्षेत्र की घटने की दर औसतन 5.5–8.7 एम/ए रही है। हाल के वर्षों में हिमनदों का आकार घटने की दर में और तेजी आई है। हिमनदों में बर्फ ज़मने में भी कमी आई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल–स्पीति में 915 किमी। क्षेत्र में हिमनदों के फोटो कुछ वर्ष तक कुछ–कुछ अन्तराल के बाद लिये गए और फिर तमाम फोटो का मिलान किया गया।

पता चला कि 1999 और 2004 के बीच यहाँ के हिमनद 0.85 मीटर प्रतिवर्ष के औसत से घट गए थे। वर्ष 2000 में नासा ने चित्र उपलब्ध कराए थे और 2004 में फ्रांस के सेटेलाईट

स्पाट–5 ने इसी इलाके के भिन्न कोणों से खींचे दो चित्र मुहैया कराए थे। स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्रैमीट्रिक तकनीक से यह अध्ययन किया गया था।

उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा हिम हिमालय क्षेत्र में उपलब्ध है और यही खतरे में हो जाएगा तो फिर किसी की खैर नहीं। हजारों हिमनदों और सैकड़ों नदियों का स्रोत है हिमालय। एशिया की अनेक महत्त्वपूर्ण नदियाँ हिमालय से निकलती हैं।

पोलर यानी ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर 72 किमी। लम्बा और 2 किमी। चौड़ा सबसे बढ़ा सियाचिन हिमनद भी हिमालय क्षेत्र में ही विद्यमान है। बल्तोरो, बायाफो, नूब्रा, हिस्पार, बंदरपूंछ, डोकरियानी, खतलिंग, दूनागिरि, तिपराबमक जैसे हिमनद सब हिमालय क्षेत्र में ही हैं। ये सब किसी–न–किसी नदी का स्रोत हैं।

वर्ष 2000 में विश्व बैंक और जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट "इंटर–सेक्टोरल वाटर अलोकेशन, प्लैनिंग एंड मैनेजमेंट" के अनुसार 2050 तक केवल ब्रह्मपुत्र, बराक और तादरी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ही ठीक–ठाक पानी रह जाएगा। इस रिपोर्ट में फुटनोट के तौर पर यह बात भी कही गई है कि 2050 तक अधिकतर हिमनद लुप्त हो जायेंगी।

इस हिसाब से हिमनदों के लुप्त होने में 35 साल ही बचे हैं। राजेन्द्र पचौरी के अनुसार तो ये हिमनद 2035 तक ही गायब हो सकते हैं। और, इस हिसाब से तो बीस साल ही बचे हैं। ऐसा होगा तो गंगा बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों का क्या होगा? चीन के अनुसंधानकर्ताओं ने तिब्बत में जो शोध किया है, उसके अनुसार तो हिमनदों के तेजी से पिघलने से उनकी स्थिति ही खराब नहीं हो रही है बल्कि बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो गई है। ❑❑

तो क्या सच में सिमट रहे हैं ग्लेशियर

हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर बर्फ के वे विशाल पिंड जो कि कम–से–कम तीन फुट मोटे व दो किलोमीटर तक लम्बे हों, हिमनद, हिमानी या ग्लेशियर कहलाते हैं। ये अपने ही भार के कारण नीचे की ओर सरकते रहते हैं। जिस तरह नदी में पानी ढलान की ओर बहता है, वैसे ही हिमनद भी नीचे की ओर खिसकते हैं। इनकी गति बेहद धीमी होती है, चौबीस घंटे में बमुश्किल चार या पाँच इंच। धरती पर जहाँ बर्फ पिघलने की तुलना में हिमप्रपात ज्यादा होता है, वहीं ग्लेशियर निर्मित होते हैं। हिमालय क्षेत्र में कोई 18065 ग्लेशियर हैं और इनमें से कोई भी तीन किलोमीटर से कम का नहीं है। हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर के बारे में यह भी गौर करने वाली बात है कि यहाँ साल में तीन सौ दिन, हर दिन कम–से–कम आठ घंटे तेज धूप रहती है। जाहिर है कि थोड़ी–बहुत गर्मी में यह हिमनद पिघलने से रहे। कोई एक दशक पहले जलवायु परिवर्तन पर अन्तरराष्ट्रीय पैनल (आईपीसीसी) ने दावा किया कि धरती के बढ़ते तापमान के चलते सम्भव है कि सन् 2035 तक हिमालय के ग्लेशियरों का नामोंनिशान मिट जाये। उदाहरण के तौर पर कश्मीर के कौलहाई हिमनद के आँकड़े देकर बताया गया कि वह एक साल में 20 मीटर सिकुड़ गया, जबकि एक अन्य छोटा ग्लेशियर लुप्त हो गया।

ठीक इसके विपरीत फ्रांस की एक संस्था ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई खास असर नहीं पड़ा है। जहाँ दुनिया के दूसरे इलाकों में कुछ हिमनद पिघले हैं तो कराकोरम क्षेत्र में बर्फ की परत की मोटाई 0.11 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी ही है। कोई चार साल पहले तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को भी दाल में कुछ काला लगा था और उन्होंने विदेशी धन पर चल रहे शोध के बजाय वीके रैना के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल को हिमनदों की हकीकत की पड़ताल का काम सौंपा था। इस दल ने 25 बड़े ग्लेशियरों को लेकर गत 150 साल के आँकड़ों को खंगाला और पाया कि हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे खिसकने का सिलसिला काफी पुराना है और बीते कुछ सालों के दौरान इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है।

पश्चिमी हिमालय की हिन्दुकुश और कराकोरम पर्वत शृंखलाओं के 230 ग्लेशियरों के समूह समस विकसित हो रहे है। पाकिस्तान के के–2 और नंदा पर्वत के हिमनद 1980 से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू–कश्मीर के केंग्रिज व डुरंग ग्लेशियर बीते 100 सालों के दौरान अपने स्थान से एक ईंच भी नहीं हिले हैं।

सन् 2000 के बाद गंगोत्री के सिकुड़ने की गति भी कम हो गई है। इस दल ने इस आशंका को भी निर्मूल माना था कि जल्द ही ग्लेशियर लुप्त हो जाएँगे व भारत में कयामत आ जाएगी। यही नहीं ग्लेशियरों के पिघलने के कारण सनसनी व वाहवाही लूटने वाले आईपीसीसी के दल ने इन निष्कर्षों पर ना तो कोई सफाई दी और ना ही इस का विरोध किया। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रो. आरके गंजू ने भी अपने शोध में कहा है कि ग्लेशियरों के पिघलने का कारण धरती का गरम होना नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो पश्चिमोत्तर पहाड़ों पर कम और पूर्वोत्तर में ज्यादा ग्लेशियर पिघलते, लेकिन हो इसका उलटा रहा है। असल में अभी तक ग्लेशियर के विस्तार, गलन, गति आदि पर नए तरीके से विचार ही नहीं किया गया है और हम उत्तरी ध्रुव पर पश्चिम देशों के सिद्धान्त को ही हिमालय पर लागू कर अध्ययन कर रहे हैं। जरा गम्भीरता से विचार करें तो पाएँगे कि हिमालय पर्वतमाला के उन इलाकों में ही ग्लेशियर ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहाँ मानव–दखल ज्यादा हुआ है। ❑

शास्त्रों में है पर्यावरण रक्षा के बेहतर उपाय

वर्तमान विश्व के सामने बैरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार इत्यादि चुनौतियां हैं। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है पर्यावरण की। इसलिए पर्यावरण इस विषय को लेकर दो वैश्विक सम्मेलन हो चुके हैं – एक क्वेटो नामक जापान के नगर में और दूसरा ब्राजील की राजधानी रियो–डी–जनरियो में। द्वितीय सम्मेलन तो सात दिन चला। जो सर्वाधिक ग्रीन–हाऊस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे प्रगत देशों से ये अपेक्षा थी कि वे इस सम्मेलन में पर्याप्त मात्रा में उत्सर्जन में कटौती की घोषणा करेंगे। किन्तु उन्होंने ऐसा करने से मुहं मोड़ लिया। उल्टे निर्धन देश (जो स्वल्प उत्सर्जक हैं) यदि अपेक्षा से और अधिक उत्सर्जन को कम करते हैं तो उन्हें ऐसा करने के बदले धन देने का प्रस्ताव प्रगत देश रख रहे थे। इसे 'कार्बन क्रेडिट' कहते हैं। कारण प्रगत देश अपने नागरिकों के उपभोगों पर आने वाली आंच को सहन नहीं करते। उत्सर्जन कम करने का अर्थ तो यहीं होता है न!

विकास दर

प्रगत देशों की यह मानसिकता क्यों बनी और प्रगतिशील देश उनका अनुसरण क्यों करते हैं – यह सभी को समझना चाहिए। प्रगत देशों ने मानव की प्रगति को भौतिक विकास तक सीमित मान लिया है। भौतिक विकास के प्रतिमान उन्होंने पश्चिम में गढ़े है। विकास के मानदण्ड़ों में एक है 'विकास दर'। भारत में हमने इन मानदण्ड़ों को हाथों हाथ लिया है। समाचार पत्रों में इसी की चर्चा चलती है कि वित्तमंत्री कितनी विकास दर पाने की घोषणा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां कितनी।

यह विकास दर अन्त में है क्या? सरल शब्दों में इसे व्याख्यायित करना है तो यह कह सकते है कि गत आर्थिक वर्ष में जितना उत्पादन हुआ उसकी तुलना में वर्तमान आर्थिक वर्ष में जितना अधिक प्रतिशत उत्पादन हुआ उसे विकास कहते हैं। इस वृद्धि में कृषि, सेवा और निर्माण इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ा जाता है। उसे सकल घरेलू उत्पाद नाम से जाना जाता है। उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब मांग अधिक होती है। मंड़ी में मांग तभी होगी जब जनता अपनी जेब ढ़ीली करेगी। अर्थात राशि का संचय त्यागकर वस्तुओं को संचय करेगी। साधनों

हमारा भारतीय चिंतन कहता है कि– 'सब भूमि गोपालकी'। हम भूस्वामी नहीं है। स्वामी ईश्वर है। अतः संकोच से साधनों को उपयोग करना चाहिए।
– श्री श्रीश देवपुजारी

की आवश्यकता उपभोगवादी प्रवृत्ति के कारण निर्माण होती है।

भारत की परम्परागत मानसिकता उपभोग प्रधान नहीं है। इसलिए विज्ञापन, स्कीमस् और क्रेडिट कार्ड के द्वारा उसे खर्च करने के लिए ललचाया जाता है। कहा जाता है कि अमेरिकन जनता ने अपनी अग्रिम दो वर्ष की औसत आय आज की खर्च कर दी है।

उपभोग पर संयम

ग्रीन हाऊस गैस या उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में चौबीस घंटे चलाए जाने वाले कल–कारखानों के द्वारा होने वाला उत्सर्जन कम करने का अर्थ हैं – उपभोग पर संयम। यह प्रगम या प्रगतिशील देशों की सरकारें करना चाहेगी तो उपभोग में मस्त जनता उन सरकारों को उखाड़े फेकेगी।

'ग्रीस' इसका उत्तम उदाहरण है। ग्रीस के नागरिकों के चार्वाक दर्शन के अनुरूप आचरण रखा। ऋण लेकर खर्च किया। जब कठोर आर्थिक अनुशासन का पालन करने की बारी आयी तो जनमत संग्रह में उसे नकार दिया।

परिणाम

आज ऋण लेकर दीपावली मनाने की वृत्ति ने ही पर्यावरण को इस समस्या को गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया है। पर्यावरण की इतनी अपरिमित हानी हुई है कि हम अकाल वर्षा और वर्षाकाल में न्यून वर्षा जैसे ऋतुचक्र के परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश भी भीषण चक्रवात और हिमवर्षा जैसे संकटों से जूझ रहे हैं। तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र जल का स्तर बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप समुद्र के किनारों की भूमि पानी निगल रही है। द्वीपों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।

विश्व के प्रसिद्ध एवं प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक श्री स्टीफन हॉकिन्स ने 2010 में दिए अपने साक्षात्कार में यह स्पष्ट रूप से चेताया था कि अगले दो

वर्तमान में हम सोच रहे हैं कि यह सृष्टि जिस किसी ने भी बनाई है वह मानव के सिर्फ उपभोग के लिए है।

सौ वर्ष में पृथ्वी मानव के लिए रहने लायक नहीं बचेगी। उन्होंने यद्यपि साक्षात्कार एक वेब–साईट को दिया था फिर भी भारत सहित पूरे विश्व में वह छपा। साक्षात्कार में स्टीफन हॉकिन्स ने आगे कहा कि यद्यपि वें नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं फिर भी हमें अभी से अन्य ग्रहों को संदेश भेजने होंगे ताकि यदि वहां मनुष्य जीवन होगा तो वे हमारी सहायता कर सके। एलियन्स के अस्तित्व पर विश्वास रखने वाला वैज्ञानिकों को एक धड़ा है और उस कल्पना को लेकर कई चलचित्र भी निर्मित हुए हैं। उनमें से एक 'अवतार' ने भारत में अच्छा व्यवसाय किया। स्टीफन हॉकिन्स के इस अनुरोध को प्रतिसाद देते हुए विश्व की कुछ एजेन्सियों ने ब्रह्माण्ड में कतिपय प्रकाशवर्ष दूर तक संदेश भेजे हैं।

ब्रह्माण्ड में स्थित अन्य ग्रहों पर बसने से भी क्या हमारा प्रकृति को असंतुलित करने का अभ्यास समाप्त होगा? क्या हम इन्द्रियों की बहिर्मुखी वृत्ति को रोकने के लिए संयम एवं अनुशासन का सहारा ले पायेंगे? यदि कर पायेंगे तो पृथ्वी को अभी भी बचाया जा सकता है। उसके लिए हमें सोच बदलनी होगी।

वर्तमान में हम सोच रहे हैं कि यह सृष्टि जिस किसी ने भी बनाई है वह सिर्फ मानव के उपभोग के लिए है। अतः सृष्टि का विनाश कर भी उपभोग करना चाहिए। अतीव उदार आधुनिक मानव केवल मानव मात्र के विषय में संवेदनशील है। अतः 'मानवता' इस मंत्र का जप करता रहता है। किन्तु जानवरों के विषय में वह हिंसक है। उनके नाश से मुहं मोडने वालों पर पुराणपंथी होने का आरोप मढ़ा जाता है। वनों को काटने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। भूमि में रासायनिक खाद मिलाकर उसे बंजर बनाने और जलप्रवाहों के जल को अपने स्वार्थ के लिए दूषित करने में वह अग्रणी है। यह सब वह तथाकथित विकास के नाम पर करता है और समाज की वाहवाही लूटता है।

इस सबकी रोकथाम तभी संभव है जब हम भारतीय दर्शनों की और लौटेंगे। 'योग' को केवल रोग ठीक करने का माध्यम नहीं मानेंगे अपितु स्वयं पतंजली ऋणी ने जो योग की व्याख्या की है – **'योगः चित्तवृत्ति निरोधः।'** उसका आचरण करेंगे। केवल स्वयं को जीवित रखने के लिए अनिवार्य चीजों का उपयोग करेंगे। सृष्टिचक्र को बाधित नहीं करेंगे। जिसका पुनर्निर्माण

संभव है उसी का उपयोग करेंगे। पेड़ की शाखा को तोड़ने से पहले उसकी क्षमा मांगेंगे।

हमारा भारतीय चिंतन कहता है कि– 'सब भूमि गोपालकी'। हम भूस्वामी नहीं है। स्वामी ईश्वर है। अतः संकोच से साधनों को उपयोग करना चाहिए। भूमि के उपयोग के पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। सागर में नाव डालने के पूर्व उसकी पूजा की जाती है। ईश्वर निर्मित सभी संसाधन केवल मेरे उपभोग के लिए निर्मित नहीं है। उस पर मेरा अधिकार नहीं है। उपनिषदों में समझाया है कि – **''अधिकं योऽभि मन्येत, स स्तेनो दण्डमर्हति।''** अर्थात् जो

आवश्यकता से अधिक ही इच्छा करता है वह दण्डनीय है कारण वह चोर है। इसलिए आज भी हमारे देश में मुकेश अंबानी के चित्र शिक्षा संस्थानों में नहीं लगाये जाते, अपितु महात्मा गांधी के लगाए जाते हैं। कारण महात्मा गांधी का जीवन संयमित था। वे केवल एक कटिवस्त्र से काम चलाते थे। आज की परिभाषा के अनुसार व सर्वाधिक अविकसित भारतीय थे। किन्तु उनका ही मार्ग अनुकरणीय है।

धर्म शब्द की साधारणतः संकुचित व्याख्या की जाती है। किन्तु धर्म का अर्थ है व्यापक होना। पुत्रधर्म का पालन करना योन मात–पिता की सेवा करना। अन्य कोई है इसलिए हम धर्म का पालन कर सकते हैं। मानवधर्म का अर्थ सृष्टि की रक्षा करना, ऐसा लगना चाहिए। इसलिए कहा गया है – **'धर्मो रक्षति रक्षितः।'** (अर्थात् जो धर्म की रक्षा यानि पालन करता है उसकी स्वयं की रक्षा होती है।)

गांधीजी एक बार प्रयाग में जवाहरलाल नेहरू जी के घर भोजन के लिए गये। भोजन के समय भी वार्ता चल रही थी। गांधीजी का भोजन समाप्त होने पर उनके हाथ धुलवाने के लिए नेहरू जी ने लोटे में पानी लिया और पानी की धार गांधीजी के हाथों पर गिराने लगे। दोनों बातों में इतने निग्न थे कि लोटे का पानी समाप्त हुआ किन्तु हाथ पूर्णतया धुले नहीं थे। नेहरू

माँ का दूध छोड़ने के पश्चात् हम गाय का दूध पीने लगते हैं। इसलिए वह गौमाता है। धान्य उपजाने वाली धरती को भी हम माता कहकर पुकारते हैं। पादस्पर्श करने के पूर्व प्रातःकाल उसकी क्षमा मांगते हैं।

जी और जल ले आए किन्तु जल के अपव्यय के कारण गांधी जी दुखी थे। इस पर नेहरू जी ने कहा कि 'गांधीजी! प्रयाग में पानी की कोई कमी नहीं है। यहां तो गंगाजी प्रवाहित है।' इस पर गांधी जी की प्रतिक्रिया थी – 'गंगाजल केवल मेरे लिए प्रवाहित नहीं हो रहा है। मुझे कम पानी से काम चलाना चाहिए था।'

भारतीय चिंतन का परिणाम ही है कि हमने हमारे जीवन को पुष्ट करने वालों को 'माता' का स्थान दिया है। कारण हमारी धारणा है – **'मातृदेवो भव।'** शुद्ध हवा अर्थात् प्राणवायु का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाली तुलसी को हमने माँ माना है। नीर के बिना जीवन संभव नहीं। अतः सरिता को हम मैया कहते हैं। माँ का दूध छोड़ने के पश्चात् हम गाय का दूध पीने लगते हैं। इसलिए वह गौमाता है। धान्य उपजाने वाली धरती को भी हम माता कहकर पुकारते हैं। पादस्पर्श करने के पूर्व प्रातःकाल उसकी क्षमा मांगते हैं।

''विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।''

हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए वृक्ष अनिवार्य है। इसलिए वृक्षों को काटना या उखाड़ना सोचकर करना चाहिए। मत्स्यपुराण में कहा गया है– **''दशकूपसमा वापी, दशवापीसमो ह्रदः। दशह्रदसमों पुत्रः, दशपुत्रसमो द्रुमः।''**

अर्थ– दश कुओं के समान बावड़ी है, दश बावड़ियों के समान एक तालाब है, दश तालाबों के समान एक पुत्र है और दश पुत्रों के समान एक वृक्ष है।

विविध पशु, पक्षी और प्राणियों जैसे– बैल, चूहा, मयुर, नाग, गरुड़, सिंह इत्यादि को हमने किसी ने किसी देवता का वाहन बना दिया है, ताकि उनकी सुरक्षा हो।

संस्कृत पढ़ने का लाभ

संस्कृत के वाक्यों को मन–मस्तिष्क पर अंकित कर और शास्त्रों को जानकर हमारी दृष्टि व्यापक और प्रकृति के साथ मेल खाने वाली बन जाती है। अतः हम संस्कृत सीखने का संकल्प लें एवं विश्व को इस संकट से बचाये।❑❑

जी.एम. सरसों के उत्पादन की मंजूरी!

मक्के की रोटी और सरसों का साग जुमला रह जायेगा

जब जाड़े के दिन आते हैं तो मैं सरसों के साग के लिए तरसने लगता हूं। जहां तक मुझे याद है जब मुझे पहली नौकरी मिली थी तो मेरी मां मुझे इतना साग भेज देती थी जो एक सप्ताह तक चल जाए। मैं हर वक्त या कम से कम दिन में एक बार साग के साथ भोजन कर सकता था। यह ऐसी आदत थी जो बचपन से ही बनी रही, लेकिन मैं अपने खान–पान के स्वाद और इच्छा की बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्द ही अपने इस पसंदीदा भोजन को मुझे भूलना पड़ेगा।

बताया जा रहा है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय आनुवंशिक रूप से परिवर्तित यानी जीएम सरसों के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति देने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई जोखिम ले पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मक्के की रोटी और सरसों के साग का लुफ्त लेने वाले लाखों उत्तर भारतीय लोग सरकार के इस कदम से बहुत निराश होंगे। आखिरकार पारंपरिक रूप से रोज की थाली का हिस्सा रही एक खाद्य फसल को आनुवंशिक रूप से परिवर्तित करने की क्या वजह हो सकती है?

वास्तव में जीएम सरसों को आम सरसों से अलग करने का कोई तरीका नहीं है कि मैं निश्चित हो सकू कि जो मैं खा रहा हूं वह आनुवंशिक तौर पर परिवर्तित नहीं है। – **डॉ. देवेन्द्र शर्मा**

वास्तव में जीएम सरसों को आम सरसों से अलग करने का कोई तरीका नहीं है कि मैं निश्चित हो सकू कि जो मैं खा रहा हूं वह आनुवंशिक तौर पर परिवर्तित नहीं है। पर्यावरण और वन मंत्रलय ने 2010 में बीटी बैंगन पर प्रतिबंध लगाया था। अगर यह नहीं किया जाता तो यह आनुवंशिक रूप से परिवर्तित पहली खाद्य फसल होती। अब पांच साल बाद अनुमति देने वाली केंद्रीय एजेंसी आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी दिल्ली विश्वविद्यालय की जीएम सरसों की एक किस्म डीएमएच–11 को हरी झंडी देने की तैयारी कर रही है। दावा है कि यह जीएम सरसों 20–25 फीसद अधिक पैदावार देती है और सरसों तेल की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है।

यह समय इन दावों की सच्चाई की परीक्षा का है। इस संदर्भ में सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि जब बीटी बैंगन की बात की जा रही थी तब तर्क था कि बैंगन की फसल एक घातक कीड़े की वजह से नष्ट हो रही है, जो इसके फल और डंठल को खा जाता है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन पिछले पांच साल में हमने देश के किसी हिस्से में बैंगन उगाने वाले किसानों द्वारा ऐसे किसी संकट के बारे

में शायद ही कभी सुना हो। जो एकमात्र समस्या है भी वह अधिक उत्पादन की है जिससे कीमतें गिरती हैं। रासायनिक खाद के मुद्दे पर हम बाद में आएंगे, पहले इस दावे की ओर देखें कि जीएम सरसों से आयात में कमी आएगी या नहीं?

जीएम सरसों को विकसित करने वाले कुछ वैज्ञानिकों को मैंने यह कहते हुए सुना है कि भारत सालाना 60 हजार करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात करता है इसलिए जीएम सरसों के बढ़े उत्पादन से आयातित तेल कम हो जाएगा। जो वस्तुस्थिति नहीं जानते उनके लिए यह लाभप्रद सुझाव है। यह सच है कि भारत सालाना 60 हजार करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात करता है, लेकिन इसकी वजह तकनीक की कमी या अधिक उत्पादन न कर पाने की समस्या अथवा पिछड़ापन नहीं है। इसका सामान्य सा कारण है कि हमने आयात शुल्क को 300 प्रतिशत घटाकर लगभग शून्य करने की अनुमति दे रखी है।

इस वजह से सस्ते आयात की बाढ़ है। सरसों समेत तमाम तिलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तिलहन टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की थी ताकि आयात घटाया जा सके। 1985 में भारत लगभग 15 हजार करोड़ का खाद्य तेल आयात कर रहा था, जो हमारी घरेलू जरूरत का लगभग 50 प्रतिशत था। पेट्रोल और उर्वरक के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा आयात बिल था। राजीव गांधी इसे कम करना चाहते थे। परिणामस्वरूप तिलहन मिशन की शुरुआत के दस साल बाद 1994–95 में भारत खाद्य तेल के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया और सिर्फ तीन प्रतिशत तेल का आयात हुआ।

आखिर अब फिर से आयात बिल बढ़कर 60 हजार करोड़ रुपये कैसे हो गया? दरअसल बाद की सरकारों ने डब्ल्यूटीओ के निर्देशों पर अत्यधिक

जीएम सरसों को विकसित करने वाले कुछ वैज्ञानिकों को मैंने यह कहते हुए सुना है कि भारत सालाना ६० हजार करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात करता है इसलिए जीएम सरसों के बढ़े उत्पादन से आयातित तेल कम हो जाएगा।

उदारीकरण की नीति के चलते आयात शुल्क घटाने शुरू कर दिए। डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुसार, भारत 300 प्रतिशत आयात शुल्क लगा सकता है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से भारत का आयात शुल्क लगभग शून्य तक ला दिया गया है। इस तरह आयात शुल्क में जबरन कटौती के कारण भारत में खाद्य तेल का आयात बढ़ते–बढ़ते आज 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। परिणामस्वरूप किसानों ने तिलहन बोना बंद कर दिया।

इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे खाद्य तेल का आयात इसलिए बढ़ा है कि हम पर्याप्त घरेलू तिलहन नहीं पैदा करते। सरसों भारत में पैदा की जाने वाली कई तिलहनी फसलों में से एक है। पिछले वर्षो में इसकी उत्पादकता और उत्पादन उछाल पर रहा है। 2010–11 में 81.8 लाख टन रिकॉर्ड सरसों का उत्पादन हुआ है। 1990–91 में इसका उत्पादन 9.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जबकि 2013–14 में औसत उत्पादन बढ़कर प्रति हेक्टेयर 12.62 क्विंटल हो गया। गुजरात में तो यह 16.95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था। सरसों का उत्पादन और बढ़ सकता है अगर किसानों को लाभकारी कीमत मिले और हर साल उत्पादन को खरीदने वाली मंडी की उचित आधारभूत संरचना बनाई जाए।

चूंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में करीब 70 प्रतिशत सरसों की फसल उगाई जाती है इसलिए किसान जो समस्या डोलते हैं वह अधिक उत्पादन और खरीदारों की कमी की है। खास तौर से राजस्थान में केंद्रीय एजेंसी नेफेड को जरूरत से ज्यादा उत्पादन और गिरती कीमत के वक्त सरसों की खरीद के लिए कई बार आगे आना पड़ता है। उपलब्ध खाद्य तेलों में सरसों का तेल स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा है। इसमें संतृप्त फैटी एसिड की मात्र सबसे कम होती है। सरसों के तेल में अपेक्षाकृत सस्ते बिनौले तेल और ताड़ के तेल की मिलावट एक बड़ी समस्या है।

इसमें तीखापन लाने के लिए लाल मिर्च के घोल की भी मिलावट की जाती है। बाजार से मैगी नूडल्स को वापस लेने के बाद मुडो कोई कारण नहीं दिखता कि सरसों के तेल में होने वाली मिलावट के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। वास्तव में सरसों तेल की गुणवत्ता में सुधार किसी आनुवंशिक परिवर्तन से नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग उद्योग में सुधार से संभव है। कहा जा रहा है कि जीईएसी आने वाले महीनों में जीएम सरसों को पूरी तरह अनुमति देने पर सक्रियता से विचार कर रही है। जीएम सरसों को लाने का कोई औचित्य न होने के बावजूद इसे लाने की कवायद को लेकर मैं यह समझ पाने में विफल हूं कि मेरे जैसे लाखों उत्तर भारतीयों को अपने पसंदीदा सरसों के साग से आखिर क्यों महरूम किया जा रहा। जीएम सरसों के आने से उसमें वह पुराना स्वाद नहीं रहेगा और यह स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी जोखिम भरा होगा। ऐसे में जीएम सरसों का साग खाने का जोखिम कौन उठाना चाहेगा? ❑❑

(लेखक देविंदर शर्मा खाद्य एवं कृषि नीतियों के विश्लेषक हैं)

प्याज पर हाहाकार, खामोश सरकार!

प्याज और आलू दो ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हम सब्जियों की सब्जियां कह सकते हैं और प्याज, जिसे कांदा भी कहते हैं, आजकल सब्जियों का राजा बन गया है। हर सब्जी में प्याज की उपस्थिति आजकल अनिवार्य–सी हो गई है। गरीब हो या अमीर, प्याज के बिना किसी की भी रसोई पूरी नहीं होती। और देश के कई हिस्सों में मैंने किसानों और मजदूरों को सिर्फ प्याज के साथ रोटी खाते हुए देखा है।

ऐसा प्याज आजकल किसानों और मजदूरों तो क्या, मध्यमवर्गीय शहरियों के लिए भी नायाब हो गया है। 80–90 रु. किलो प्याज खरीदकर कौन खा सकता है? प्याज की मंहगाई की वजह से कुछ साल पहले कुछ पार्टियां राज्यों के चुनाव में हार गई थी लेकिन दिल्ली की सरकार को कोई खास डर नहीं है, क्योंकि चुनाव अभी चार साल दूर हैं। असली सवाल यह है कि प्याज के थोक व्यापारियों पर यह सरकार यमराज की तरह टूट क्यों नहीं पड़ती? कहीं इस सरकार के नेता भी प्याज वालों की चांदी तो नहीं काट रहे हैं?

देश में प्याज की सबसे बड़ी मंडी महाराष्ट्र के लसालगांव में है। इस मंडी पर चार–पांच व्यापारियों का एकाधिकार–सा है। वे मनमानी करते हैं। ये जमाखोर व्यापारी प्याज की कीमत को एकदम उछाला दे देते हैं। एक विधिवत जांच से पता चला है कि इन महाव्यापारियों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है। ये ही लोग थोक–व्यापारियों, मंडियों, दलालों, भंडारों और रेल्वे–एजेंटों को अपने काबू में रखते हैं। खुदरा दुकानदार भी मुनाफाखोरी में इनका पूरा–पूरा साथ देते हैं। देश में एक करोड़ 70 लाख टन प्याज खपता है और इस साल इसका उत्पादन हुआ है– एक करोड़ 90 लाख टन। 20 लाख टन प्याज अतिरिक्त है,इसके बावजूद 10–15 रु. किलो का प्याज 80 रु. में कैसे बिक रहा है?

यदि सरकारें सजग होती तो प्याज के सारे जमाखोर जेल की हवा खा रहे होते और उनका प्याज जब्त करके 10 रु. किलो में बिकवा दिया जाता। हमारे नेताओं में नैतिक शक्ति का भी अभाव है। किसी भी नेता ने जनता से यह नहीं कहा कि वह सिर्फ दो–तीन सप्ताह तक प्याज न खाए। देखिए, प्याजवालों के आंसू झरने लगते या नहीं? ❑❑

गरीब हो या अमीर, प्याज के बिना किसी की भी रसोई पूरी नहीं होती और देश के कई हिस्सों में मैंने किसानों और मजदूरों को सिर्फ प्याज के साथ रोटी खाते हुए देखा है।

– वेद प्रताप वैदिक

भारतीय हथकरघा उद्योग

ब्रांड के साथ बाजार में उतरने की तैयारी

हथकरघा वस्त्र और हथकरघा बुनकर भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह उद्योग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। भारत में कृषि के बाद हथकरघा सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र 43.31 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है जिसमें से करीब 23.77 लाख व्यक्ति हथकरघा से जुड़े हैं, जिसमें से 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 45 प्रतिशत अन्य पिछड़ें वर्गों से हैं। वर्ष 2013–14 में हथकरघा क्षेत्र में 71160 लाख वर्ग मीटर उत्पादन दर्ज किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में कुल 35470 लाख वर्ग मीटर (अप्रैल–सितंबर, 2014) का उत्पादन दर्ज किया गया था।

ये क्षेत्र देश के वस्त्र उत्पादन में करीब 15 प्रतिशत का योगदान करता है और देश की निर्यात आय में भी सहयोग करता है। दुनिया में हाथ से बुने हुए कपड़े का 95 प्रतिशत भारत से आता है। इस कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी को हस्तांतरित करके बनाए रखा गया है। इस क्षेत्र की क्षमता, इसकी विशिष्टता, उत्पादन के लचीलेपन, नवाचारों के लिए खुलापन आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलनशीलता और इसकी परंपरा की संपदा में निहित है।

हालांकि, हथकरघा उद्योग को तेजी से बढ़ते आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को नई दिशा देने की आवश्यकता है। समकालीन उपभोक्ता संदर्भों के अनुसार दोषमुक्त उच्चगुणवत्ता वाले हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन के साथ–साथ उचित मजदूरी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी इस व्यवसाय को चुनें। स्थायी आधार पर इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर यह भी अत्यंत आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के विश्वास को जीतने के लिए नए डिजाइन के साथ गुणवत्तायुक्त कपड़ों का उत्पादन किया जाए।

भारत में कषि के बाद हथकरघा सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र ४३.३१ लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है जिसमें से करीब २३.७७ लाख व्यक्ति हथकरघा से जुड़े हैं। – **जैकब अब्राह्म**

''भारत हथकरघा ब्रांड'' कच्चे माल, प्रसंस्करण, अलंकरण, बुनकर डिजाइन और अन्य मानदंडों के अलावा उपभोक्ताओं के विश्वास को हासिल करने के लिए सामाजिक और पर्यावरण के अनुकूल हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अब तक के प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोहों के एक अंग के तहत हाल ही में चेन्नई में भारत हथकरघा ब्रांड का शुभारंभ किया। इसमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करना है –

- उच्चगुणवत्ता, दोषमुक्त, हाथ से बुने हुए, प्रामाणिक 'उत्तम किस्म' के उत्पादों का उत्पादन
- पूर्ण दोषमुक्त
- प्रामाणिक पारंपरिक डिजाइन
- पर्यावरण पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं
- सामाजिक अनुपालन

लाभः

- ग्राहक को विशिष्टता के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाएगा।
- भारत के हाथ से बने प्रामाणिक कपड़ों के लिए एक अलग बाजार स्थापित करने और स्त्री/पुरूष के डिजाइन उत्पादों के अनुसार थोक खरीदारों और निर्यातकों को स्रोत गुणवत्ता वस्त्रों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।
- बुनकर, सीधे बाजार के साथ वार्तालाप के द्वारा थोक आदेश और अधिक मजदूरी प्राप्त करने में सक्षम होगा।
- यह महिलाओं और वंचित वर्गों को भी सशक्त बनाएगा।

ब्रांडिंग के लिए चिन्हित उत्पाद

साड़ी – *सूतीः* जमद्दानी, तांगेल, शांतिपीरी, धनियाखाली, विचित्रपुरी, बोम्केइ, कोटपाद, पोचमपल्ली, वेंकटगिरि, उप्पडा, सिद्धिपेट, नारायणपेट, मंगलागिरि, चेतिनाद, बलरामपुरम, केसरगौड़, कुथमपल्ली, चेंदमंगलम, धोती।

रेशमः बलूचारी, मूंगा सिल्क, सल्कच सिल्क, खांडुआ, बेरहमपुरी, बोमकेइ सिल्क, बनारस ब्रोकेड, तनचोइ, बनारसी, बूटीदार, जंगला, बनारसी कटवर्क, कोचमपल्ली, धर्मावरम, कांचीपुरम, अरनी सिल्क, मोलकामुरू, पेथानी, पटोला, चंपा सिल्क, आशावल्ली सिल्क, सेलम सिल्क (धोती), उप्पडा, जमदानी।

सूती रेशम साड़ीः चंदेरी, महेशवरी, कोटा दोरिया, इलकाल, गदवल, कोवइ कोरा, कोटन।

परिधान सामग्री–*कपासः* ओडिशा इकाट, पोचमपल्ली

रेशम– तंचौइ, बनारसी, कटवर्क, ओडिशा इकाट, पोचमपल्ली इकाट, टस्सर फैब्रिक।

बैड शीट – ओडिशा इकाट, पोचमपल्ली इकाट

स्कॉर्फ/शॉल/चादर– कनी शॉल, किन्नोरी शॉल, कुलु शॉल, तंगालिया शॉल, कुट्च शॉल, वंगखेइ फी।

ब्रांडिंग प्रक्रिया

निम्नलिखित संस्थान ''भारत हथकरघा'' ब्रांड पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतू पात्र होंगे –

- हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ईमानदार कंपनियां/संस्थान, जिनमें शामिल हैं
- प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां
- स्व–सहायता (एसएचजी), भागीदारी, निर्माता कंपनियां, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)
- बुनकर उद्यमी
- कपड़ों और अन्य वस्तुओं के निर्माता इस शर्त के साथ कि वे 'भारतीय हथकरघा' ब्रांडेड कपड़ों का उपयोग करेंगे और सिलाई, मानक आकारों आदि के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अतिरिक्त गुणवत्ता का अनुपालन करेंगे।

इस संबंध में आवेदनों को बुनकर सेवा केंद्र अथवा वस्त्र समिति के कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में जमा कराया जा सकता है। आवेदन में प्रस्तुत किए गए तथ्यों की जांच के बाद 30 दिनों के भीतर लोगों के साथ ब्रांड प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वस्त्र नमूनों की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच की जाएगी। आवेदन भरने के 30 दिनों के भीतर यदि कोई कमी है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। ब्रांडिंग आमतौर पर नियम और शर्तों के अधीन 3 वर्षों के लिए वैध होगी और इसके पश्चात इसका पुनः नवीनीकरण कराया जाएगा। ब्रांडिंग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ब्रिकी के लिए प्रत्येक मद पर लोगों और लेबल्स (स्टीकर्स) लगाए जाएंगे। ❑❑

प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोहों के एक अंग के तहत हाल ही में चेन्नई में भारत हथकरघा ब्रांड का शुभारंभ किया।

गीता प्रेस पर संकट मजबूरी या षडयंत्र

गीता प्रेस के संकटग्रस्त होने की खबर से भारतीय जनमानस मर्माहत हैं, क्योंकि गीता प्रेस की भूमिका सनातन संस्कृति की संरक्षण की रही है। हालांकि संचालकों व ट्रस्टियों ने साफ कर दिया है कि गीता प्रेस बंद होने वाला नहीं है, न ही इसे बंद करने की कोई योजना है। जबकि गीता प्रेस के कुछ कर्मचारी उच्च वेतनमान और सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। फिर भी कुछ लोग गीता प्रेस को संजीवनी देने के प्रयास में गंभीरता से लगे हैं। ऐसी भागीरथी भूमिका निभाने वालों का कहना है कि गीता प्रेस को किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होने दिया जायेगा। उनकी मांग है कि गीता प्रेस को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए, सरकार को सचेत रहकर गंभीर भूमिका निभानी चाहिए। षडयंत्री संकट से गीता प्रेस को मुक्ति दिलायी जानी चाहिए। जबकि कुछ तथाकथित सेकुलर लोग और छद्म मीडिया के पत्रकार मजदूरों की हड़ताल को हवा दे रहे हैं और इस बात के प्रयास में है कि गीता प्रेस पर ताला लग जाये। उनका कुतर्क है कि 'गीता प्रेस' हिन्दू भारत बनाने की मुहिम चलाने वाला छापाखाना है, वो यह भी कहते है कि अयोध्या में बाबरी ढ़ाचा ढहाकर राममंदिर का जो आंदोलन चला उसकी पृष्ठभूमि में गीता प्रेस ही थी। यही लोग गीता प्रेस को भी सांप्रदायिक करार देने में लगे है।

मालूम हो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा शुरू की गई गीता प्रेस हिन्दू धर्म से जुड़े साहित्यों को दशकों से प्रकाशित कर रही है। हर हिन्दू परिवार के घर में कम पैसे में धार्मिक ग्रंथ पहुंचाने का श्रेय गीता प्रेस को ही जाता है। वर्षों से गीता प्रेस रामायण, हनुमान चालीसा समेत तमाम धार्मिक पुस्तकों तथा ग्रंथों को प्रकाशन निर्बाध करती आ रही है। यह कहना गलत है कि गीता प्रेस के संचालकों के पास आर्थिक अभाव है जिसके कारण गीता प्रेस जैसे संस्थान को बंद करने की नौबत आ जाये। हकीकत है कि यहां करोडों–अरबों रुपये चढ़ावे या दान के रूप में आते है। यदि कोई ऐसी नौबत आती भी है तो सनातन धर्म के लिए काम करने वाले मंदिरों और ट्रस्टों से आर्थिक सहायता गीता प्रेस को कभी भी मिल सकती है।

गीता प्रेस को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए, सरकार को सचेत रहकर गंभीर भूमिका निभानी चाहिए। षडयंत्री संकट से गीता प्रेस को मुक्ति दिलायी जानी चाहिए।
– स्वदेशी संवाद

गीता प्रेस का प्रबंधन स्पष्ट कह रहा है कि इन दिनों सोशल साइट्स पर गीताप्रेस के बंद होने की खबर सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश है। गीता प्रेस के ट्रस्टी देवीदयाल का

कहना है कि प्रेस के बंद होने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इस वर्ष भी गीताप्रेस अन्य वर्षों की तरह से ढाई से पौने तीन करोड़ पुस्तकें प्रकाशित करेगी। देवीदयाल का यह भी कहना है कि हमारी पुस्तकों की लोकप्रियता की वजह कम कीमत के साथ बेहतर प्रिंटिंग भी है। गीताप्रेस का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। हम सद्प्रचार के लिए पुस्तकें छापते हैं।

गीता प्रेस की किताबों की बिक्री आज भी प्रतिदिन 50 हजार प्रतियों से ज्यादा है। धार्मिक किताबों में आज की तारीख में सबसे ज्यादा मांग रामचरित मानस की है। लेकिन सेकुलर तबका और छद्म मीडिया समूह इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

गीता प्रेस सिर्फ सनातन संस्कृति का ही संरक्षक नहीं है, बल्कि भारत के पुर्नजागरण का भी प्रतीक है। गीता प्रेस देश की आजादी के आंदोलन में विचारशील सक्रियता की बहुत बड़ी भूमिका थी, आजादी के आंदोलन में आंदोलनकारियों को प्रेरक साहित्य उपलब्ध कराने, अंग्रेजों द्वारा डर, भय और उत्पीड़न के हथकंडे से दबायी गयी जनता को आंदोलन की राह पर लाने के लिए प्रेरक, क्रियाशील वैचारिक धरातल तैयार कराया था। गीता प्रेस ने अखंड भारत की कल्पना की थी। अखंड भारत के लिए उसने वैचारिक सक्रियता दिखायी थी। आजादी के आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस से लेकर छोटे–बड़े सभी आजादी के सेनानियों को अखंड भारत के सामरिक और विकासात्मक महत्व को समझाया था। द्विराष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ भी गीता प्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया था और अखंड भारत को खंड–खंड करने के लिए साजिश का पर्दाफाश किया था, इसके दुष्परिणामों को लेकर भी चेताया था।

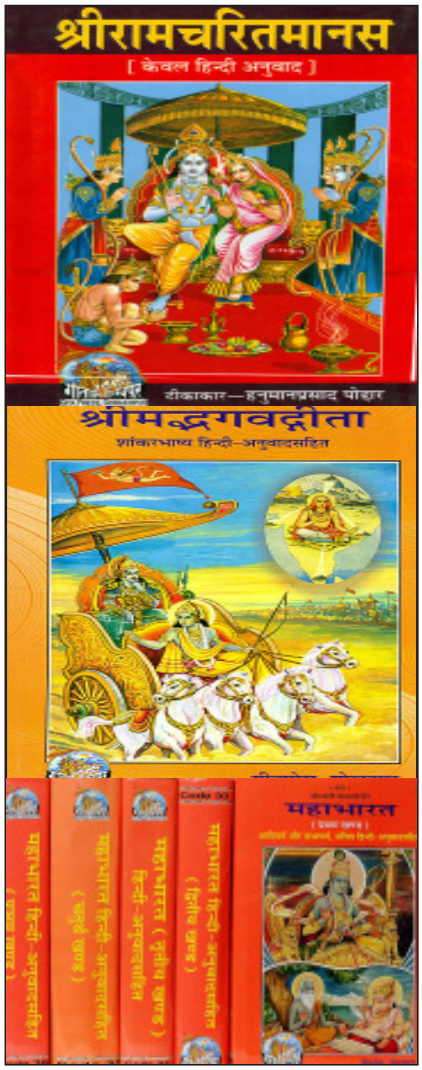

प्रेस के बंद होने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इस वर्ष भी गीताप्रेस अन्य वर्षों की तरह से ढाई से पौने तीन करोड़ पुस्तकें प्रकाशित करेगी।

1946 में गीता प्रेस ने पं. मदन मोहन मालवीय की मृत्यु के पश्चात मालवीय पर एक विशेष अंक निकाला था, इस विशेष अंक में मालवीय के योगदानों का उल्लेख तो था ही इसके साथ ही साथ दंगों में हिन्दुओं पर हुए अत्याचार, हिन्दू महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की घटनाओं का प्रमाण के साथ उल्लेख था। जैसे ही यह विशेष अंक सामने आया वैसे ही पूरे भारत भर में प्रतिक्रिया हुई। अंग्रेजी सरकार और कांग्रेस के नेताओं की फजीहत हुई। कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से कहकर उस विशेष अंक पर प्रतिबंध लगवा दिया था। देश का विभाजन हुआ और अंखड भारत का सपना चकनाचूर हुआ पर गीता प्रेस का राष्ट्र के प्रति समर्पण और सक्रियता कम नहीं हुई थी। जब हिन्दू कोड बिल लाया गया तो गीता प्रेस ने उसका जमकर विरोध किया था, समान नागरिक संहिता की बात कही थी।

गीता प्रेस के प्रकाशकों से राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, बल्लभ भाई पटेल, गोविन्द बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय के मधुर संबंध थे और ये सभी देश के पुर्नजागरण में गीता प्रेस की भूमिका को कालजयी मानते थे।

गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्धार किसी भी पुरस्कार लेने के विरोधी थे। इसीलिए हनुमान प्रसाद पोद्धार पुरस्कारों और सरकारी पदों के लालच से दूर होकर देश के पुर्नजागरण में सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे।

गीता प्रेस आज भी व्यक्तिगत या सरकारी विज्ञापन नहीं लेती, कारपोरेट विज्ञापन वह स्वीकार नहीं करती। किसी भी प्रकार का वह सरकारी सुविधा या मदद नहीं लेती। कारपोरेट चंदा भी स्वीकार नहीं करती। अपने संसाधनों व दान आदि से अपनी जरूरतों को पूरा करती हैं।

गीता प्रेस को हर प्रकार के हथकंडे और मिथ्याचार से बचाया जाना चाहिए। गीता प्रेस की भूमिका राष्ट्र के प्रति समर्पण है। गीता प्रेस जन–जन तक पहुंच रखता है। इसलिए गीता प्रेस के खिलाफ साजिश करने और गीता प्रेस को सांप्रदायिकता का प्रतीक बताने के हथकंडे कामयाब नहीं होने वाले हैं।❑❑

बंदेमातरम् क्रांति का देव मंत्र

बंकिम चन्द्र चटर्जी ने ब्रिटिश सरकार के आधीन डिप्टी मज्सिट्रेट पद पर रहते हुए बंदेमातरम् की रचना की और अपने उपन्यास 'आनन्द मठ' में उसे शमिल किया, जिसका पहला प्रकाशन उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'बंग दर्शन' में 1882 में हुआ। एक बार उनके प्रकाशन विभाग के मैनेजर बंग दर्शन पत्रिका में कुछ बचे हुए स्थान के भरपाई के लिए उनसे मिले और बंदेमातरम् एक कागज पर लिखी हुई देखकर के बंकिम को बताया कि आप इसे संशोधन कर दीजिए, इसी को हम पत्रिका में छापेंगे। बंकिम जी ने मैनेजर की तरफ देखा और बताया, ''तुम इसको संशोधित करना चाहते हो, यदि तुम और 25 वर्ष जीवित रहोगे तो इस कविता के द्वारा उत्पन्न तूफ़ान को देख पाओगे। बंकिम ने अपनी बड़ी पुत्री को बताया कि एक दिन संपूर्ण देश में बंदेमातरम के द्वारा ही क्रांति की शुरूआत होने वाली है। बंकिम 1894 तक जीवित रहे और इस कालावधि में आनन्द मठ का 5 बार संस्करण निकल चुका था।

बंदेमातरम संगीत के रूप में गाने के बाद रविन्द्र नाथ टैगोर ने बताया कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें गहरे रोमांच का अनुभव हुआ। सरलादेवी चौधरानी ने 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में बंदेमातरम् गाया था। बंदेमातरम एक मंत्र है। तंत्रविद्या के लेखक सर जॉन उड्रोफ (कलकत्ता हाई कोर्ट के भूतपूर्व न्याधीश) के अनुसार तंत्र, मंत्र और जंत्र के संयोग से मंत्र का क्रियान्वयन होता है। सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी ने घोषणा की कि स्वदेशी बंदेमातरम का व्यवहारिक स्वरूप है।

श्री अरविन्द और बंदेमातरम्

बंदेमातरम् सिर्फ राष्ट्रगान ही नहीं है बल्कि यह एक पवित्र मंत्र है। इसके लेखक (आनन्द मठ के उपन्यासकार) बंकिमचन्द्र चटर्जी एक ऋषि थे। अरविन्द ने आगे कहा कि शायद किसी सन्यासी ने बंकिमचन्द्र को यह मंत्र दिया। इस मंत्र कोई नवीन अविष्कार नहीं है। यह एक पुराने मंत्र जो लुप्त हो गया था, उसकी पुनर्रचना है। नवाकिशन नामक एक

बंदेमातरम् सिर्फ राष्ट्रगान ही नहीं है बल्कि यह एक पवित्र मंत्र है। इसके लेखक बंकिमचन्द्र चटर्जी एक ऋषि थे।
– श्री सरोज मित्र

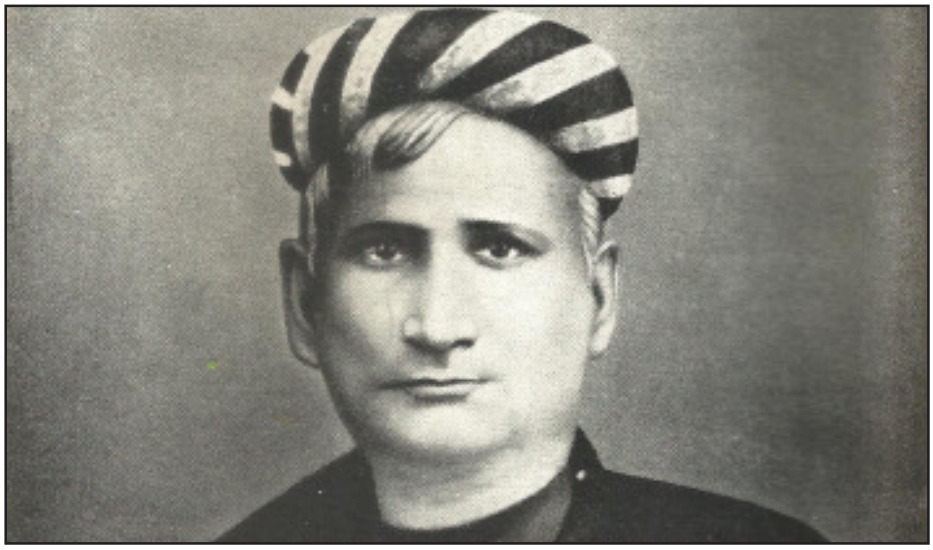

व्यक्ति के विश्वासघात के कारण इस मंत्र का उद्‌गम नहीं हो पाया।

बंकिम के जीवनकाल में इस मंत्र का प्रचार नहीं हुआ, परन्तु उनकी भविष्यवाणी के अनुसार जल्दी ही यह संपूर्ण भारत में फैल गया। पहली बार में इस संगीत का अर्थ लोगों की समझ में नहीं आया, लोग इसे सिर्फ देश भक्ति संगीत समझते रहे। देश की मुक्ति के लिए सबकुछ त्याग करने का आह्‌वान करने वाले इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अरविन्द ने कहा व्यक्ति के शरीर के जैसा ही राष्ट्र का भी शरीर या कोष होता है, जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर वैसे ही बंकिमचन्द्र ने बंदेमातरम् मंत्र के अंतर्निहित अर्थ को लोगों के सम्मुख रखा। – (**बंदेमातरम् पत्रिका, जनवरी 29, 1908**)

आंदोलन का भविष्य

जब एक महान जाति धूल से ऊपर उठती है तब एक संजीवनी मंत्र की आवश्कता होती है। बंदेमातरम् मात्रभूमि के प्रति भक्ति जगाने वाला मंत्र है। विंद्धाचल में रहने वाले सन्यासियों ने सर्वप्रथम इस मंत्र को उजागर किया था। कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण यह मंत्र लुप्त हो गया। जब 1897 ई. में एक बड़ा भूकम्प आया, तो विंद्धाचल के सन्यासियों ने एक शब्द सुना जिसको उन्होंने ईश्वर का आदेश मानकर प्रकट किया। इस मंत्र ने लोगों का हृदय स्पर्श किया और पूरे राष्ट्र को जगाया। – (**बंदेमातरम् पत्रिका, फरवरी 19, 1908**)

7 अगस्त 1905 कलकत्ता की सड़कों पर लोगों ने बंदेमातरम् का घोष करते हुए बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंदेमातरम् उस दिन से संघर्ष का हथियार बन गया।

7 अगस्त 1905 श्री अरविन्द ने कहा

हमारे अन्दर जो आत्मा है वह इतिहास रचता है, भाग्य निर्माण करता है। भौतिक प्रकृति या घटनाक्रम समय और स्थान के नियंत्रण में आत्मा के अनुरूप बाह्य स्वरूप प्रदान करता है। देश की आजादी उस दिन तय हो जाती है जिस दिन उसकी आत्मा इसे अनुभव करती है, न कि जिस दिन प्रशासनिक परिवर्तन होता है और वाह्य रूप से आजादी दिखती है। 7 अगस्त 1905 को ही देश आजाद हो गया था जब बंकिमचन्द्र के इस मंत्र का लोगों ने मर्म समझ लिया था। मन से लोग मातृभूमि के प्रति समर्पित हो गए थे फिर तो अंग्रेजों के शासन से मुक्ति महज समय की बात रह गई थी। बायकट या विरोध भी आजादी का ही एक व्यवहारिक रूप है। 7 अगस्त 1905 को जब हम लोगों ने बायकट की घोषणा की, यह केवल आंशिक संघर्ष मात्र ही नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्वाधीनता का आह्‌वान था। इसलिए 7 अगस्त 1905 भारतीय राष्ट्रीय जागरण का दिन है, जिस दिन भारत अपनी आत्मा को खोज पाया। उसी दिन भारतीय राष्ट्रीयता की बुनियाद रखी गयी। – (**बंदेमातरम् पत्रिका, अगस्त 6, 1907**)

बंदेमातरम की शेष कहानी अगले अंक में

स्वदेशी पत्रिका का नवंबर अंक श्रद्धेय ठेंगड़ी जी को समर्पित

श्रद्धेय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जयंती 10 नवंबर को है। इस अवसर पर इस राष्ट्रमनीषी को स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से भावभिनी शब्दांजलि। स्वदेशी पत्रिका का नंवबर अंक स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी का समर्पित होगा। आपमें से अधिकतर लोगों का कहीं न कहीं कभी न कभी ठेंगड़ी जी से व्यक्तिगत मुलाकात या सार्वजनिक स्थलों पर मिलने का अवसर प्राप्त होगा। या ऐसा भी हुआ होगा कि श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के जीवन के किसी अंश से आप प्रभावित हुए होंगे। हमारी कोशिश है कि नवंबर का स्वदेशी पत्रिका का अंक श्रद्धेय ठेंगड़ी जी की यादों का धरोहर बने और इसमें आपके अनुभव एवं संवेदनाओं को भी प्रर्याप्त स्थान मिले। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके पास श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के संस्मरण से जुड़े किसी भी वाक्या, उद्धरण या स्मृति के रूप में कोई तस्वीर या पत्र वगैरह हो तो आप हमें अवश्य भेंजे।

हमारा पता है

'धर्मक्षेत्र', शिव शक्ति मंदिर, सेक्टर–8, आर.के.पुरम्, नई दिल्ली–110022,
दूरभाषः 011–26184595, ई–मेलः **swadeshipatrika@rediffmail.com**

(25 सितंबर श्री दीनदयाल जयंती के विशेष उपलक्ष्य में)

'अनियंत्रित उपभोग गैरबराबरी का कारण'

पं. दीनदयाल उपाध्याय न केवल एक राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता थे बल्कि वे एक अर्थशास्त्री भी थे। अपने आर्थिक चिंतन की व्याख्या करने के लिए उन्होंने 'भारतीय अर्थनीतिः विकास की एक दशा' नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में अर्थनीति की विवेचना करते हुए उन्होंने अपने एकात्मक मानव के अर्थाभास की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। समाज में अर्थ के प्रभाव व अभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को अर्थायाम कहा गया। उन्होंने कहा कि अर्थ का अभाव मनुष्य को चोर बनाता है तथा अर्थ का प्रभाव भोग विलास में आसक्ति उत्पन्न कर देता है। अतः आवश्यक है कि अधिकाधिक उत्पादन, समान वितरण तथा संयमित उपभोग की प्रवृत्ति पैदा की जाये – यही आर्थिक क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्य है।

पं. दीनदयाल ने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी जिसे उन्होंने अर्थ संस्कृति कहा। वे कहते हैं मानव जीवन में उत्पादन, वितरण एवं उपभोग ये तीन क्रियाएं उसके आर्थिक जीवन को रूपायित करती है। अनियंत्रित उपभोग वितरण में विषमता व लूट को प्रेरित करता है। उत्पादन की भी कोई मर्यादा नहीं रहती। यह असंस्कृत आर्थिक जीवन हैं उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र है – अपरमात्रिक उत्पादन, समान वितरण तथा संयमित उपभोग।

उत्पादन की मर्यादा के लिए वे कहते थे –

1. उपभोग की आवश्यकता एवं अपेक्षित बचत के लिए पर्याप्त उत्पादन, अपरमात्रिक उत्पादन होता है। यह उत्पादन की मर्यादा है।
2. जिस उत्पादन को खपत के लिए बाजार खोजना पड़े, लोगों में उपभोग की लालसा जगानी पड़े वह सामाजिक संस्कारों में असंतुलन उत्पन्न करता है।
3. प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमा है। उनका उच्छंखल दोहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति में एक संतुलन है, प्रकृति अपने पद्धति से क्षय की पूर्ति करती रहती हैं। मानव इतनी तेजी से इसका विनाश कर रहा है कि न तो प्रकृति क्षतिपूर्ति कर पाती है और न उसका संतुलन ही ठीक पाता है।

पं. दीनदयाल ने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी जिसे उन्होंने अर्थ संस्कति कहा। वे कहते हैं मानव जीवन में उत्पादन, वितरण एवं उपभोग ये तीन क्रियाएं उसके आर्थिक जीवन को रूपायित करती है।
– डॉ. विजय वशिष्ठ

वितरण में समानता के संबंध में वे कहते थे –

1. वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई ये पांच आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की पूरी होनी ही चाहिए।
2. अधिकतम व न्यूनतम आय का नियत अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए।
3. वितरक निकायें, उत्पादक व उपभोक्ता के साथ संतुलन वाली हों।

उपभोक्ता के विषय में उनकी मान्यता थी कि –

1. संयमित उपभोग का तात्पर्य है स्वस्थ शरीर की आवश्यकता अनुकूल उपभोग। इन्द्रिय लोलुपता को जगाकर किया जाने वाला उपभोग शरीरिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों

से घातक होता है।

2. अनियमित उपभोग असमान वितरण का कारण है। उपयोग में संयम तथा सादा जीवन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण है। उत्पादन, उपभोग का नियंत्रण नहीं करता बल्कि उपभोग ही उत्पादन का नियंत्रण करता है।
3. आर्थिक अभाव तथा प्रभाव दोनों ही उपयोग को असंयमित करते हैं। अतः अर्थव्यवस्था ऐसी चाहिए जो जीवन के अर्थायाम की सम्पूर्ति करते।
4. संयमित उपभोक्ता के संयोजन के लिए समाज में योग्य शिक्षा एवं संस्कार की व्यवस्था आवश्यक है। सांस्कृतिक आनन्द उपभोग को संयमित करता है।

दीनदयाल जी ने बम्बई के एक प्रसिद्ध भाषण में अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों के बारे में कहा था कि –

1. प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की आश्वस्ति तथा राष्ट्र के सुरक्षा सामर्थ्य की व्यवस्था हो।
2. इस स्तर के उपरांत उत्तरोत्तर समृद्धि, जिससे व्यक्ति और समाज को वे साधन उपलब्ध हो सके जिनसे वे अपनी चिति के आधार पर विश्व की प्रगति में योगदान कर सके।
3. इन लक्ष्यों की सिद्धि के लिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को साभिप्रयास आजीविका का अवसर देना तथा प्रकृति के साधनों का मित्वययता के साथ उपभोग करना।
4. राष्ट्र के उत्पादन–उत्पादनों का विचार कर अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करना।
5. यह व्यवस्था मानव की अवहेलना न कर, उसके विकास में साधक हो तथा समाज के सांस्कृतिक व अन्य जीवन मूल्यों की रक्षा करें।
6. विभिन्न उद्योगों में राज्य, व्यक्ति तथा अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का निर्णय व्यावहारिक आधार पर हो।

दीनदयाल जी समय–समय पर आर्थिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उन्होंने श्रम को धर्म कहा। उनका कहना था कि श्रम करना मनुष्य का मूलभूत कर्त्तव्य है। इसी प्रकार वे मानते थे कि मनुष्य को श्रम करने का अधिकार देना राज्य का मूलभूत कर्त्तव्य है। इसी आधार पर वे कहते थे कि हमारी योजनाओं का लक्ष्य होना चाहिए – **सबको काम।** वे पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों का ही विरोध करते थे। उनका कहना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले आर्थिक क्षेत्र पर आधिपत्य जमाकर फिर परोक्ष रूप से राज्य पर अधिकार करती है जबकि समाजवाद राज्य को ही संपूर्ण उत्पादनों का स्वामी बना देता है। दोनों व्यवस्थाएं व्यक्ति के प्रजातंत्रीय अधिकार एवं उसके स्वस्थ विकास के प्रतिकूल हैं।

वे आर्थिक क्षेत्र में केन्द्रीयकरण के विरूद्ध एवं लोकतंत्र के समर्थक थे। उनका कहना था कि प्रत्येक को वोट जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निकाय है, वैसे ही प्रत्येक को काम, यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदण्ड है। यंत्रचालिक औद्योगिकरण की मर्यादा को स्पष्ट करते हुए उपाध्याय एक समीकरण प्रस्तुत करते हैं – प्रत्येक को काम को सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाए तो सम वितरण की दिशा सुनिश्चित हो जाती है और हम विकेन्द्रीयकरण की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिकरण को उद्देश्य मानकर चलना गलत है। विदेशी पूंजी के बारे में वे कहते हैं कि हमारे देश को विदेशी पूंजी के बल पर औद्योगिकृत नहीं किया जाना चाहिए। विदेशी पूंजी के राजनैतिक के अलावा आर्थिक प्रभाव भी अशुभ होते हैं। विदेशी पूंजी का विनियोग स्वदेशी श्रम का शोषण करता है।

विकेन्द्रीकरण को दीनदयाल जी

दीनदयाल जी आर्थिक चिंतन की दृष्टि से भी बहुत सन्नद्ध राजनेता थे। वे न्यास सिद्धान्त के पक्षपाती हैं।

अर्थव्यवस्था का केन्द्रीय मुद्दा मानते थे। विकेन्द्रीकरण से ही हम सामाजिक न्याय, स्वदेशी व स्वावलम्बन को प्राप्त कर अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा के परिवर्तन को बताना हो तो वह है – विकेन्द्रीकरण और स्वदेशी। वे आग्रहपूर्वक प्रतिपादित करते हैं कि भारत के स्व का साक्षात्मकार किए बिना हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पायेंगे।

दीनदयाल जी आर्थिक चिंतन की दृष्टि से भी बहुत सन्नद्ध राजनेता थे। वे न्यास सिद्धान्त के पक्षपाती हैं। राष्ट्रहित, उद्योगहित, श्रमिक हित व उपभोक्ता हित के पक्षधर हैं। वे आर्थिक संस्कृति के नियामक थे।

उनका आर्थिक विचार मानव्य प्रधान एवं समाजपरक है। आर्थिक विषयों में दीनदयाल जी ने बहुत क्रमबद्ध गहन एवं गवेषणात्मक साहित्य का सृजन किया है। राष्ट्रीय अखण्डता व सुरक्षा के विषय में जितनी ख्याति प्राप्त कर सके, उनको आर्थिक चिंतन उतना लोक प्रसिद्ध नहीं हो सका। आज की आर्थिक समस्याओं का समाधान हम दीनदयाल जी की अर्थसंस्कृति के माध्यम से कर सकते हैं। उत्पादन में, उपभोग में संयम तथा वितरण में समानता के द्वारा वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। आवश्यकता है दृढ़ इच्छाशक्ति ही। सौभाग्य से वर्तमान में केन्द्र में दीनदयाल जी के विचारों के समर्थकों की सरकार है। मेरा आग्रह है कि आर्थिक निर्णय लेते समय उनके विचारों का भी ध्यान रखा जाए। तभी हम दीनदयाल जी को उनकी जन्मशताब्दी वर्ष में सच्ची श्रद्धांजली दे सकेंगे। ❑❑

सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011

गरीबों की बदहाली का जिम्मेदार कौन?

देश में एक तरफ जहां अरबपतियों, पूंजीपतियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं अब तक बारह पंचवर्षीय योजनाओं में लाखों करोड़ रूपये खर्च करने के बावजूद ग्रामीण बेहद गरीबी में जीने को मजबूर हैं। देश के तमाम राजनीतिक दल जिन गांवों, गरीबों, किसानों और मजदूरों को लेकर शोर–शराबा मचाते हैं वे उनकी दशा सुधारने में असफल रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 की ताजा सरकारी रिपोर्ट इसी बात की पुष्टि करती है। इसके अनुसार गांवों में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है और आजीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 17.9 परिवारों में से 75 फीसदी परिवारों का अधिकतम वेतन 5 हजार रूपये से कम है वहीं 40 फीसदी परिवार भूमिहीन हैं और मजदूरी करते हैं। जाहिर है कि गांव बदहाल हैं। लेकिन उसके सुधार के लिए योजना बनाने वाले कर्ता–धर्ता और तमाम मंत्री, सांसद और विधायक मालामाल हो गये। गांवों की इस बदहाली की जिम्मेदारी उन सभी दलों को लेनी होगी जो कभी न कभी केन्द्र अथवा राज्यों में सत्ता में रहे हैं और किसानों और गांवों का हितैषी बनने का दावा करते रहे हैं। आजादी के 68 वर्षो बाद भी देश की इतनी बड़ी आबादी किसी तरह गुजर–बसर कर रही है। इनकी दशा को सुधारे बिना देश तरक्की कैसे कर सकता है?

क्या यह हमारे राजनेताओं के लिए लज्जा की बात नहीं है कि शासन–सत्ता में आते ही उनकी सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ने लगती है और देश के करोड़ों घरों में दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता है और लोग भूखे सो जाते हैं। देश की लगभग 37 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे बदहाली में गुजर बसर कर रही है। मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भी देश के आठ राज्यों – बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गरीबों की संख्या 42 करोड़ है जो अफ्रीका के 26 निर्धनतम देशों की संख्या से भी अधिक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के शिकार 84 देशों की सूची में भारत का 67वां स्थान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले १७.६ परिवारों में से ७५ फीसदी परिवारों का अधिकतम वेतन ५ हजार रूपये से कम है वहीं ४० फीसदी परिवार भूमिहीन हैं और मजदूरी करते हैं। जाहिर है कि गांव बदहाल हैं।

– निरंकार सिंह

बेरोजगारी की दर 10.7 फीसदी है और यदि यही हाल रहा तो यह 2020 तक 30 फीसदी तक पहुंच जायेगी। उधर हर साल लगभग नौ लाख लोगों की मौत दूषित जल और प्रदूषण से हो जाती है। निरक्षरता, बालश्रम और आर्थिक विषमता के मामले में भी हमारी स्थिति बहुत खराब है। विश्व की 90 फीसदी गंदी बस्तिया विकासशील देशों में हैं जिनमें से 37 फीसदी बस्तियां सिर्फ भारत और चीन में है। ये आंकड़े हमारे राजनेताओं के राज चलाने की क्षमता पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं।

एक राष्ट्र के रूप में हमने अपने विकास के लिए संसदीय लोकतंत्र की पद्धति अपनायी है। भारतीय संविधान परिषद ने जनता के नाम पर संकल्प लिया है कि भारत एक प्रभुता सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बने। उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त हो तथा उनके बीच व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं राष्ट्र की एकता व अखण्डता को सुनिश्चित करते हुए बन्धुता बढ़ाने की भावना का प्रचार किया जाए। ये लक्ष्य और उद्देश्य लोकतंत्र का एक प्रेरक एवं चुनौतीपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आजादी के छह दशक के बाद भी केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मंत्री अपनी जनता के लिए पानी, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सके। नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय खुद भ्रष्टाचार में भागीदार बन गये। सांसद और विधायक निधि में भ्रष्टाचार ने संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को पतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इस तरह से जिन लोक प्रतिनिधियों को नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी थी वे अपने दायित्व को निभाने में असफल साबित हो रहे

आजादी के छह दशक के बाद भी केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मंत्री अपनी जनता के लिए पानी, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सके।

हैं। अंग्रेजों के समय जिस ढंग से जिस प्रकार शासन चल रहा था आज उससे भी बदतर स्थिति है। छोटा से छोटा राजकर्मचारी भी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उल्टे वह उन पर धौंस जमाता है और पहले की तरह उनसे रिश्वत वसूलता है।

कुल मिलाकर हमारा संसदीय लोकतंत्र सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के निहित स्वार्थ पर टिका है। लोक कल्याणकारी राज्य की भावना कहीं दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि हमारी राज्य व्यवस्था लोगों के लिए रोजी रोजगार का प्रबन्ध करने में असफल साबित हो रही है। आम आदमी का जब भी किसी सरकारी विभाग से पाला पड़ता है तो उसकी जेब खाली हो जाती है। हालत यहां तक पहुंच गयी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक मामले में सरकारी तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता प्रकट करते हुए कहना पड़ा कि – 'कुछ भी बिना पैसे के नहीं होता' यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं है।' मंत्री से लेकर संतरी तक और राज्य का छोटे से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी देखते ही देखते मालामाल हो जाए और हमारी राज्य व्यवस्था को यह दिखाई नहीं दे तो इसे क्या कहा जायेगा। हमारे कई वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री, नौकरशाह सी.बी.आई. जांच के दायरे में है। लेकिन हमारी व्यवस्था में किसी भी मामले में किसी बड़े नेता और नौकरशाह को सजा नहीं मिलती है। अब यदि कानून को बड़े–बड़े नेताओं और अफसरशाहों की आलीशान कोठियां, शापिंग काम्पलेक्स, कृषि फार्म, महंगी विदेशी गाड़ियां और तमाम नामी और बेनामी सम्पत्तियां दिखाई नहीं देती हैं तो इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है।

जरूरत इस बात की है कि केन्द्र और राज्य सरकारें संविधान के निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस संकल्प के साथ कदम उठायें। देश और संसदीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए उन्हें यह करना ही पड़ेगा। यह संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की इस दशा को समझा है और वे उसे सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। तकनीक के क्षेत्र में उनकी योजनाएं ऐसी हैं यदि उन्हें ठीक से लागू किया तो गांव और शहर की तस्वीर बदल सकती है। ❑❑

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस - 8 सितंबर पर विशेष

पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ...

वर्ष 2011 की जनगणना मुताबिक 74.04 प्रतिशत भारतीयों को अक्षरज्ञानी कहा जा सकता है। वर्गीकरण करें, तो 82.14 प्रतिशत पुरुष और 65.46 महिलाओं को आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आगे बढने और जिंदगी की रेस में टिकने के लिए अक्षर ज्ञान जरूरी है। इस संदर्भ में उनके इस विश्वास से शायद ही किसी को इंकार हो कि इसमें साक्षरता की भूमिका, मुख्य संचालक की हो सकती है। किंतु क्या साक्षरता का मतलब सिर्फ वर्णमाला के अक्षरों और मात्राओं को जोडकर शब्द तथा वाक्य रूप में पढ़ लेना मात्र है ? क्या मात्र अक्षर ज्ञान हो जाने से हम हर चीज के बारे में बुनियादी तौर पर ज्ञानी हो सकते हैं? नहीं!

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'साक्षरता और टिकाऊ समाज' को इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का मुख्य विचार बिंदु तय किया गया है। गौर कीजिए कि यह बिंदु, हमारे उत्तर का समर्थन करता है। टिकाऊ विकास के स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में सक्षमता हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विचारकों ने भी सिर्फ साक्षरता को नहीं, बल्कि सीखने का वातावरण को न्यूनतम आवश्यकता के रूप में महत्व दिया है। 'सीखने का वातावरण' – हम भारतीयों को इसके मंतव्य पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वे कहते हैं कि टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए व्यापक ज्ञान, कौशल, व्यवहार और मूल्यों की आवश्कता है। यह सच है कि ये सभी आवश्यकतायें हमें टिकाऊ विकास की भी बुनियादी आवश्यकतायें हैं। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने खास निवेदन किया है कि टिकाऊ विकास के भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें यह वर्ष साक्षरता और टिकाऊ विकास का जुडाव व सहयोग सुनिश्चित करने हेतु समर्पित करना चाहिए।

क्या साक्षरता का मतलब सिर्फ वर्णमाला के अक्षरों और मात्राओं को जोडकर शब्द तथा वाक्य रूप में पढ़ लेना मात्र है?

– अरूण तिवारी

अक्षर ज्ञान से कितना आगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ?

आप संतुष्ट हो सकते हैं कि यह बात भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा बहुत पहले समझ ली गई थीय इसीलिए साक्षरता मिशन के कार्यक्रम, आज अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं हैंय इसीलिए मिशन के संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान की संकल्पना की। इन अभियानों को नवसाक्षर को खासतौर पर आसपास के परिवेश और जरूरी कौशल

के बारे में साक्षर और सक्षम बनाने के उद्देश्य से डिजायन किया गया है।

प्रकृति प्रेमी इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि भारत सरकार के साक्षरता मिशन ने अन्य विषयों के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को विशेष उद्देश्य के रूप में चिन्हित किया है। किंतु इस बात आप असंतुष्ट भी हो सकते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम इस दिशा में रस्म अदायगी से बहुत आगे नहीं बढ़ सके हैं। कहने को आज भारत के 424 एवम् 176 जिले क्रमशः संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता अभियानों की पहुंच में है। किंतु भारत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सामाजिक पहल की सुस्त दर बताती है कि जरूरत रस्म अदायगी से कहीं आगे बढ़ने की है। बगैर औपचारिक–पंजीकृत संगठन बनाये ऐसी पहल के उदाहरण तो और भी कम हैं।

उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में भी आज प्रकृति और प्राकृतिक संरक्षण के मसलों को लेकर अज्ञान अथवा भ्रम कायम हैं।

कितने निरक्षर हम ?

दरअसल, हमें साक्षरता की आवश्यकता हवा, पानी, नमी, जंगल, पठार, पहाङ से लेकर अनगिनत जीवों और वनस्पतियों.. सभी की बाबत् है। क्या यह सच नहीं कि अक्षर ज्ञान रखने वाले ही नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में भी आज प्रकृति और प्राकृतिक संरक्षण के मसलों को लेकर अज्ञान अथवा भ्रम कायम हैं। नदी जोङ ठीक है या गलत ? कोई कहता है कि 'रन ऑफ रिवर डैम' से कोई नुकसान नहींय कोई इसे भी नदी के लिए नुकसानदेह मानता है। कोई नदी को खोदकर गहरा कर देने को नदी पुनर्जीवन का काम मानता हैय कोई इसे नदी को नाला बना देने का कार्य कहता है। किसी के लिए नदी, नाला और नहर में भिन्नता भी साक्षर होने का एक विषय है। कोई गाद और रेत के फर्क और महत्व को ही नहीं समझता। कोई है, जो गाद और रेत निकासी को सब जगह अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। कोई मानता है कि जितने ज्यादा गहरे बोर से पानी लाया जायेगा, वह उतना अच्छा होगा। किसी की समझ इससे भिन्न है।

पानी–पर्यावरण साक्षरता के विषय कई

ज्यादातर लोग आज मानते हैं कि 'आर ओ' प्रक्रिया से प्राप्त पानी को आपूर्ति किए जा रहे पानी तथा भूजल से बेहतर हैंय जबकि कई विशेषज्ञ 'आर ओ' प्रक्रिया से गुजरे पानी को सामान्य अशुद्धि जल से ज्यादा खतरनाक मानते हैं। वे कहते हैं कि 'आर ओ वाटर' बॉयलर और बैटरी के लिए मुफीद है, जीवों के पीने के लिए नहीं। उनका तर्क है कि 'आर ओ' प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली झिल्ली सिर्फ खनिजों को ही वहीं नहीं रोक लेती, बल्कि ऐसे जीवाणुओं का भी वहीं खात्मा कर देती हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में के लिए सहयोगी हैंय जिन्हे प्रकृति ने हमें असल पानी के साथ मुफ्त दिया है। लिहाजा, 'आर ओ वाटर' इसी तरह 'मिनरल वाटर' के नाम पर मिल रहे बोतलबंद पानी को लेकर भी मत भिन्नता है। 'आर ओ वाटर' और 'मिनरल वाटर' नहीं, तो शुद्ध पानी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या ? पानी को ठंडा करने के लिए मिट्टी का मटका, रेफ्रिजरेटर से बेहतर विकल्प क्यों है ? मिट्टी का मटका पानी को शीतल ही नहीं करता, नाइट्रेट जैसी अशुद्धि से मुक्त करने का काम भी करता है। क्या यह हमारे साक्षर होने का विषय नहीं।

क्या सच नहीं कि हमें ऐसे कितने मसलों पर साक्षर होने की जरूरत है ? इन मसलों पर एक राय न होना ही जल के मामले में हमारे निरक्षर होने का पुख्ता सबूत है।

तकनीकी डिग्री–डिप्लोमा प्राप्त कितने ही लोग ऐसे हैं, संचयन ढांचे बनाने के लिए जिन्हे न विविध भूगोल के अनुकूल स्थान का चयन करना आता है और न ही ढांचे का डिजायन बनाना। यदि हमारे सरकारी ढांचें में यह निरक्षरता न होती, तो मनरेगा के ज्यादातर ढांचें बेपानी न होते। भारत की कृषि को भूजल पर निर्भर बनाना अच्छा है या नहरी जल अथवा अन्य सतही ढांचों के जल पर ? क्या इसका उत्तर, पूरे भारत के लिए एक हो सकता है ? यदि हम अनुकूल माध्यम के बारे में साक्षर होते, तो 'स्वजल' परियोजना के तहत् उत्तराखण्ड के ऊंचे पहाडी इलाकों में इंडिया मार्का हैण्डपम्प लगाने की बजाय, चाल–खाल बनाते।

अन्य प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हमारी साक्षरता पर गौर कीजिए।

कोई प्राकृतिक जंगल को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो किसी को इमारती जंगल बेहतर लगता है। किसी को गिद्ध, गौरैया, गाय, कौआ, बाघ, भालू, घडियाल, डॉलफिन से लेकर अनेकानेक प्रजातियों की संख्या घटने से कोई फर्क नहीं पडता, अनेक हैं जिन्हे फर्क पडता है। अभी दिल्ली के एक अस्थमा पीडित व्यक्ति से तीन ऐसे पौधों की खोज की, जिन्हे लगाकर हम अपने आसपास की हवा को साफ कर सकते हैं। किंतु हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते।

कहना न होगा कि पानी–हवा समेत कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनके दैनिक उपयोग और संरक्षण को लेकर भारतीय समाज के हर वर्ग को साक्षर होने की जरूरत हैय नेता, अफसर, इंजीनियर, ठेकेदार, किसान से लेकर शिक्षक, वकील और डॉक्टर तक। यदि हम इनके उपयोग और संरक्षण को लेकर

बाजार, कभी किसी ग्राहक को स्वावलंबी नहीं बनाता।

साक्षर हो जायें, तो न मालूम अपना और अपने देश का कितने आर्थिक, प्राकृतिक और मानव संसाधनों को सेहतमंद बनाये रखने में सहायक हो जायें!

सद्ज्ञान से स्वावलंबन

हमारी दैनिक समस्याओं को लेकर आज हमारे समक्ष पेश ज्यादातर विकल्प, खरीद–बिक्री की रणनीति पर आधारित हैं। बाजार, कभी किसी ग्राहक को स्वावलंबी नहीं बनाता। अतः सच यही है कि इन विषयों की साक्षरता और स्वयं करने का कौशल ही हमें इन मामलों में स्वावलंबी बनायेंगे। अतः हमें सिर्फ पानी–पर्यावरण ही नहीं, बल्कि विकास को टिकाये और बेहतरी की दिशा में गतिमान बनाये रखने के हर पहलू के प्रति साक्षर होने के प्रयास तेज कर देने चाहिए। रास्ते और रणनीति क्या हो ? इस पर सभी को अपने–अपने स्तर पर विमर्श और जमीनी काम शुरु कर देने चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर इस बाबत् हम स्वयं चेतें और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लोक चेतना केन्द्रों को भी चेतायें।

मददगार तकनीक, साझे से समग्रता

यूनेस्को के महानिदेशक ने इस बाबत् अपने सभी सहभागी देशों से निवेदन किया है कि संपूर्ण साक्षरता लक्ष्य हासिल करने हेतु वे मोबाइल फोन समेत उपलब्ध आधुनिक तकनीक को एक ताजा अवसर के तौर पर लें। उम्मीद है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण, संचार और सूचना से संबद्ध मंत्रालय इस दिशा में कुछ सोचेंगे और संयुक्त रूप से कुछ करेंगे। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

दिखने लगा असर
बेटी बचाओ अभियान का

भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में बालिकाओं के घटते हुए शिशु लिंग अनुपात ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर बेटी को नहीं बचाया तो भविष्य में बेटी, मां और जननी का अस्तित्व खतरे में है। जनगणना के अनुसार 0–6 वर्ष आयु वर्ग के 1000 लड़कों कें अनुपात में 918 लड़कियों का आंकड़ा होना पाया गया है, जोकि अब तक का सबसे कम है। हरियाणा में यह अनुपात 830 था। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ो में लड़कियों की घटती संख्या के बारे में जो आंकड़े दर्शाये गये हैं उससे प्रतीत होता है कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री की पहल पर हरियाणा ने शुरू की अनोखी योजना – बेटी बचाओ, बेटी पढाओं। इसका मुख्य उद्देश्य था लडकियों के जन्म के प्रति सकारात्मकता, शिक्षा और पोषण देने के लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना। यह योजना हरियाणा के असंतुलित लिंगानुपात वाले 12 जिलों अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, सोनीपत, करनाल, पानीपत, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी और झज्जर में शुरू की गई।

कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अब तक 2316 जागरूकता अभियान आयोजित किए जा चुके है। गांवों में 15204 गुडडा–गुडडी बोर्ड लगाये गये जिनमें मास के दौरान हुये जन्म का पंजीकरण तथा गांव में लिंग अनुपात को दर्शाया गया ।

सरकार द्वारा उपरोक्त उठाए गए कदमों से कार्यक्रम को सफलता प्राप्त हो रही है तथा शिशु लिंग अनुपात में भी सुधार हो रहा है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरूआत जनवरी 2015 में की गई और इसे प्रोत्साहित करने के लिए इसे कई और योजनाओं से जोड़ दिया गया है। जिनमें – सुकन्या समृद्धि खाता योजना, हरियाणा कन्या कोष, आपकी बेटी – हमारी बेटी, 0–6 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीकरण, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु आप्रेशन मुस्कान, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012। ❑❑

बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना के बाद लिंग अनुपात में आश्चर्यजनक वृद्धि

क्र.	जिला	शिशु लिंग अनुपात		
		जनवरी 2015	जून 2015	अंको का सुधार
1	रिवाड़ी	716	796	80
2	झज्जर	800	847	47
3	यमुनानगर	850	888	38
4	भिवानी	845	873	28
5	सोनीपत	816	843	27
6	फरीदाबाद	823	848	25
7	कुरूक्षेत्र	831	852	21
8	कैथल	877	893	16
9	पंचकुला	892	901	9
10	फतेहाबाद	899	904	5

चीन को पछाड़ेगा भारत

इस साल भारत की आर्थिक विकास दर उम्मीद से अधिक रहने की संभावना है। इस आर्थिक विकास दर के साथ ही भारत 2015 में चीन से भी आगे निकल जाएगा। इतना ही नहीं, 2016 में भारत चीन से और अधिक आगे निकल जाएगा। इस बात की भविष्यवाणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने की है। दोनों का ही मानना है कि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 फीसदी तक पहुंच सकती है, जो पिछले साल 7.2 प्रतिशत थी। वहीं दूसरी ओर, 2016 के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े अलग–अलग हैं। आईएमएफ के अनुसार 2016 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत रह सकती है, जबकि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत की आर्थिक विकास दर 2016 में 7.9 प्रतिशत हो जाएगी।

एक जानकारी पर 15 लाख तक का इनाम

सरकार आपसे एक जानकारी मांगे और आपको उसके लिए 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाए तो कैसा लगेगा। निश्चित ही इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। सरकार ने टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया तरीका निकाला है। अगर आपको किसी टैक्स चोर की जानकारी है और ऐसे किसी भी व्यक्ति की आप जानकारी देते हैं तो सरकार आपको 15 लाख रुपए का इनाम देगी। वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार का मानना है कि इस पहल से बड़े टैक्स चोरों को पकड़ने में सफलता मिल सकती है। सरकारी नियम के मुताबिक, सूचना देने वालों को कुल बकाया टैक्स राशि से 10 फीसदी हिस्सा या अधिक का इनाम दिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़, पंजाब में भी मीट पर रोक

जैन धर्म के त्योहार की वजह से मीट की खरीद–फरोख्त पर अब छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी बैन लगाया गया। मुंबई की दो नगर पालिका, गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान में पहले से ही बैन लग चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मांस की खरीद–फरोख्त पर 9 दिनों का बैन लगाया है। जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व और गणेश चतुर्थी को देखते हुए प्रदेश में 10 से 18 सितम्बर तक जानवरों को काटने और मांस बेचने और खरीदने पर बैन लगाया गया है। इससे पहले, रायपुर नगर निगम ने भी 8 सितंबर को शहर में 10 से 17 सितम्बर तक मांस–मटन की बिक्री पर बैन लगाया था।

दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हुई भारत की महिला

भारतीय मूल की एक उद्यमी को फार्च्यून पत्रिका की 10 महिला नवोन्मेषी, अग्रणी, उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली महिला उद्योगपतियों की 2015 की सालाना सूची में शामिल किया गया है। पायल कडाकिया दो साल पुरानी स्टार्टअप क्लासपास की मुख्य कार्यकारी

और सह–संस्थापक हैं जो उपभोक्ताओं को उनके क्षेत्र में हजारों बुटीक फिटनेस केंद्रों की जानकारी मुहैया कराता है।

फार्च्यून ने एक बयान में कहा, 'क्लासपास सिर्फ 2 साल पुराना है लेकिन इसने अब तक अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन में जिम और स्टूडियो में 70 लाख सत्र की बुकिंग की है।' कडाकिया ने कहा कि वह बैले सीखना चाहती थीं लेकिन न्यूयार्क सिटी में बैले प्रशिक्षण की जानकारी हासिल करने में नाकाम रहीं जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। पत्रिका में उनके हवाले से कहा गया 'उस वक्त मुझे लगा कि ज्यादातर लोगों को अपनी रुचि और शौक से जुडने में परेशानी होती होगी।'

संकट में भारत का हीरा उद्योग

भारत की हीरानगरी सूरत में सालभर पहले ही अपने सैकड़ों कर्मचारियों को बोनस के तौर पर फियेट कार, घर और ज्वैलरी देकर भारत की डायमंड पॉलिश करने वाली कंपनी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन इस साल यहां हीरा उद्योग की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है।

दुनिया के करीब 80 फीसदी हीरों की पॉलिश करने वाले शहर में इस

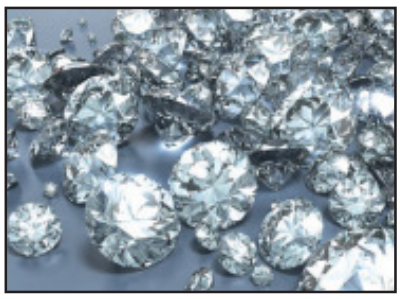

साल इस तरह के किसी बोनस के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दरअसल, चीन के उपभोक्ताओं की ओर से लग्जरी आभूषणों की मांग कम होने से ज्वैलरी का स्टॉक काफी ज्यादा हो गया है। इसके चलते जून तक हीरा पॉलिश करने वाले करीब 5000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, जबकि हजारों और बेरोजगार हो सकते हैं। पॉलिश करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि चीनी ज्वैलरों ने लाखों डॉलर का कारोबार प्रभावित किया है।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मंजूर, सरकारी कर्मचारियों का डीए 6 फीसदी बढ़ा

घरों में रखे सोने को बाहर निकालने के लिए कैबिनेट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में गोल्ड मोनेटाइजेशन और सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम को अनुमति दी गई। आम आदमी से लेकर मंदिर, ट्रस्ट और बड़े बिजनेसमैन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इससे बेकार पड़ा सोना बैंकिंग सिस्टम में आएगा जिसका लाभ देश को होगा, वहीं लोगों को गोल्ड जमा कराने पर ब्याज मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 फीसदी बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है।

रेलवे के अच्छे दिन

आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान

बढाते हुए सरकार भारतीय रेल में 8.5 लाख करोड़ रुपये का विशाल निवेश करेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार भारतीय रेल की तस्वीर बदलना चाहती है। सिन्हा ने विपक्ष से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित कराने में सहयोग करने को कहा, ताकि देश में एक नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कारोबार में तेजी आएगी। यहां ऑटो–मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं के संगठन (एकमा) की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा ध्यान दिये हुए है। उन्होंने कहा, भरतीय रेल में लंबे समय से चल रहे निवेश के अभाव के बाद हमने केवल इसी क्षत्र में ही 8.5 लाख करोद रुपये के निवेश का निर्णय किया है। यह एक असाधारण निर्णय है और यह रेलवे की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा।

BSNL ब्राडबैंड की न्यूनतम स्पीड होगी 2MBPS

सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल एक अक्टूबर से अपने ब्राडबैंड ग्राहकों को कम से कम दो एमबीपीएस की स्पीड देगी। इसके लिए किसी तरह का

अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अपने परिचालन को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही कंपनी इस समय कम से कम 512 केबीपीएस स्पीड की पेशकश करती है। मार्च 2014 से मार्च 2015 के दौरान कंपनी के लगभग 1.78 करोड़ वायरलैस तथा 20 लाख से अधिक लैंडलाइन ग्राहक टूट गए।

वन रैंक वन पेंशन से 16,000 करोड़ का बोझ

वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) का सरकार पर ठीकठाक बोझ पड़ने

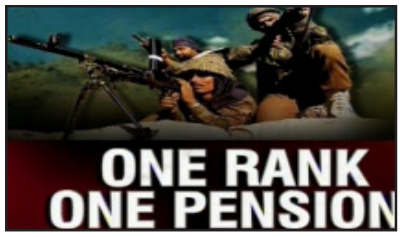

जा रहा है। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में इसकी कुल कॉस्ट 16,000 करोड़ रुपए आएगी। एचएसबीसी ने कहा है कि इसका असर फिस्कल डेफिसिट टार्गेट पर दिखाई दे सकता है। हालांकि, सरकार ने इस तरह के अनुमान को नकारते हुए कहा है कि उसके फिस्कल डेफिसिट टार्गेट पर ओआरओपी का असर नहीं होगा। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ओआरओपी को स्वीकार कर लिया है। देश के रक्षा कर्मी काफी समय से एक रैंक के लिए एक तरह की पेंशन की मांग करते आ रहे थे। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा रक्षा कर्मियों की मांग स्वीकार करने के बाद अब उसे वर्तमान पेंशन से अधिक पेंशन राशि देने के साथ ही 2014 के जुलाई से एरियर भी देना होगा।

हाइक ने शुरू की मुफ्त ग्रुप कालिंग सुविधा

दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख हस्ती

सुनील मित्तल के पुत्र केविन मित्तल के नेतृत्व वाले हाइक मैसेंजर ने एक मुफ्त समूह कालिंग सुविधा पेश की जिसके तहत 100 लोगों तक से संपर्क की सुविधा होगी। कंपनी ने एक बयान में कहा यह सुविधा एंड्रायड पर 4जी और वाय–फाय पर काम करेगी जबकि आईओएस तथा विंडोज को इस दायरे में यह इस साल के अंत तक लाया जाएगा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नेट निष्पक्षता पर अपनी रपट में ओटीटी इकाइयों द्वारा पेश की जाने वाली वॉयस काल की सुविधा को इस नियम के तहत लाने का प्रस्ताव किया है। समूह कालिंग की पेशकश के साथ हाइक ने वॉयस ओवर इंटरनेट (वीओआईपी) पर से बीटा टैग भी हटा दिया है। हाइक मैसेंजर के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी केविन भारती मित्तल ने कहा अब एक बटन दबाकर आप एक ही काल में 100 लोगों से जुड़ सकते हैं। बिना किसी पिन, बिना कोई और नंबर डायल किए और लोगों को होल्ड पर रखे आप इनसे जुड़े रह सकते हैं। समूह में कालिंग इतनी आसान कभी नहीं थी।

650 खरब रूपये तक हो सकता है काला धन!

काले धन के नए कानून का असर दिखने लगा है। टैक्स चोरी करके भारत और दूसरे देशों में काला धन छिपाने वाले अमीर भारतीयों में खलबली मच गई है। कानून के शिकंजे से बचने के लिए वे नई तरकीबें आजमां रहे हैं, धन छिपाने के लिए नए ठिकाने तलाश रहे हैं और फर्जी कंपनियों का सहारा ले रहे हैं। विदेशी खातों में छिपे काले धन का खुलासा करने के लिए तय की कई आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसमें कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, इसलिए पिछले कुछ हफ्तों में टैक्स चुराने वालों की बेचौनी ज्यादा दिख रही है। हालांकि अब तक सिर्फ एक उद्योगपति ने टैक्स और जुर्माने का भुगतान किया है।

काला धन कानून से बचने के लिए कई व्यापारी नए–नए तरीके अपना रहे हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों को 182 दिनों के लिए विदेश भेज देते हैं। इससे वे अप्रवासी बन जाते हैं और विदेश में खाते खोलने और व्यापार की छूट मिल जाती है। इससे काला धन छिपाना आसान हो जाता है। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने नया तरीका खोज निकाला है। मिश्रित बीमा उत्पादों के जरिए गैरकानूनी पैसे को दुबई और सिंगापुर भेजा जा रहा है। इसके बाद इसे कानूनी बनाकर वापस मंगा लिया जाता है।

सस्ते घर खरीदने में ईपीएफओ करेगा मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के न्यासी एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे जिससे तहत अंशदाताओं को सस्ते घर खरीदने के लिए अपने भावी भविष्य निधि योगदान को गिरवी रखने की अनुमति दी जा सकती है। ईपीएफओ की नीति निर्धारण संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ईपीएफ अंशधारकों के लिए आवास सुविधा के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा। प्रस्तावित योजना के तहत अंशदाता, बैंक–आवास एजेंसी और ईपीएफओ के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा। समिति का सुझाव है कि इस योजना के तहत अंशदाता बैंक या आवास वित्त कंपनियों से मिले ऋण और संपत्ति को गिरवी रखकर घर खरीदेंगे। इसमें

सुझाव दिया गया है कि लाभार्थियों को इस योजना के तहत आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की योजनाओं के फायदे भी दिए जाएं।

हालांकि समिति ने सुझाव दिया कि यह योजना संगठित क्षेत्र में कम आय वाले कामगारों के लिए है जो ईपीएफओ के अंशदाता हैं। इसके अलावा श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला सीबीटी अपनी बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमित राशि बढ़ाकर 5.5 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा जो फिलहाल 3.6 लाख रुपए है। सीबीटी के पास अंतिम सुझाव के लिए भेजने के लिए उपसमिति कल इसकी जांच करेगी।

सरकार करेगी 1 हजार टन प्याज का आयात

देश में प्याज की ऊंची कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने एक हजार टन अतिरिक्त प्याज का आयात करने का निर्णय किया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को प्याज की उपलब्धता और उसकी कीमतों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसी बैठक में एक हजार टन अतिरिक्त प्याज के आयात का निर्णय लिया गया।

2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार होगा भारत

भारत में कारों की बिक्री आनेवाले 15 सालों तक 90 लाख पर पहुँच जाएगी। चीन तथा अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार होगा। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम ने बाजार अध्ययन एजेंसी पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इस समय दुनिया भर में हर साल छह करोड़ 80 लाख कारें बिकती हैं। इनमें 29 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ चीन सबसे बड़ा बाजार है। कुल माँग का 24 प्रतिशत यूरोपीय देशों, 11 प्रतिशत अमेरिका, सात प्रतिशत जापान तथा चार प्रतिशत (26 लाख) भारत से आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक दुनिया में कारों की बिक्री बढ़कर आठ करोड़ 60 लाख तथा वर्ष 2030 तक 15 करोड़ पर पहुँच जायेगी।

कॉल ड्रॉप हुई तो मिलेंगे 1 से 5 रुपए

तेजी से बढ़ती कॉल ड्राप की समस्या से उपभोक्ताओं को निजात देने के लिए सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। सरकार प्रत्येक कॉल ड्रॉप पर

संचार कंपनियों से ग्राहकों को एक से पांच रुपए तक भुगतान करने को कह सकती है। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) जल्द ही परिपत्र जारी करेगा। निजी दूरसंचार कंपनियों ने तर्क दिया है कि कॉल ड्रॉप अवश्य होती है लेकिन ग्राहकों को आर्थिक नुकसान नहीं होता है। कॉल ड्रॉप का मुद्दा तब बहस का विषय बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चिंता जताई थी। मोदी ने दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा था कि इस समस्या को दूर करने के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। केंद्र ने विशेषकर मेट्रो शहरों में कॉल ड्रॉप को गंभीर समस्या माना है। दिल्ली के कुछ इलाकों में यह अधिक भयावह हो गई है। मुंबई जैसे मेट्रो व छोटे कस्बों में भी यह समस्या तेजी से बढ़ी है।

एशिया में सबसे कम सैलेरी देने वालों देशों में शामिल है भारत

पेशेवर सेवा फर्म टावर्स वाटसन का कहना है कि भारत में प्रवेश स्तर का वेतन एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे कम में से एक है। टावर्स वाटसन की डेटा सेवा ने एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है। इसके अनुसार भारत में औसत मासिक शुरुआती वेतन 400 डालर (24,000 रूपए) है। दक्षिण कोरिया व सिंगापुर की तुलना में यह पांचवें हिस्से से भी कम है। इसके अनुसार स्नातक भारतीय कर्मचारियों का शुरूआती वेतन एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे कम में से एक है। इस सूची मे पहला स्थान सिंगापुर और उसके बाद जापान का है। भारत की स्थिति फिलीपींस और इंडोनेशिया से मजबूत है।

मुंबई धमाकों में 12 लोग दोषी करार

2006 के मुंबई धमाकों के सिलसिले में मकोका कोर्ट ने 12 लोगों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल 13 अभियुक्त थे। कोर्ट से बाहर निकलकर सरकारी वकील राजा ठाकरे ने संवाददाताओं को बताया, 'कुल 13 में से एक अभियुक्त को बरी कर दिया गया है. बाकी को मकोका के तहत दोषी पाया गया है। इसमें मौत की सजा का प्रावध ाान भी है. सजा के बारे में सोमवार को बहस होगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।' उन्होंने बताया कि सरकारी वकीलों ने कुल 192 गवाह पेश किए थे जबकि बचाव पक्ष ने 51 गवाह पेश किए।

गांव वाले खुद चलाते हैं रेलवे स्टेशन

उत्तरी–पश्चिमी रेलवे ने जयपुर डिविजन के स्टेशन रशीदपुरा खोरी को 2005 में घाटे के चलते बंद कर दिया था। यह स्टेशन सिर्फ ग्रामीणों की इच्छा शक्ति और मेहनत के बूते चल रहा है। गांव वाले न सिर्फ रेलवे के दिए टार्गेट से ज्यादा के टिकट खरीदते हैं बल्कि स्टेशन की देखरेख, यात्रियों के लिए पानी और अन्य चीजों की व्यवस्था भी करते हैं और तो और टिकट काटने का काम और बेटिकट यात्रियों को रोकने का काम भी इन्हीं का है। ❑❑

दिल्ली प्रांतीय सम्मेलन

(23 अगस्त 2015)

रविवार दिनांक 23 अगस्त 2015 को शहनाई बैक्वट हॉल सीलमपुर में 150 महिलाओं सहित 450 की भागीदारी के साथ दिल्ली प्रांत सम्मेलन संपन्न हुआ। देश की अर्थव्यस्था से जुड़े ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण विषयों – वर्तमान परिदृश्य में स्वदेशी की भूमिका, विदेशी निवेश, भूमि अधिग्रहण, जी.एम. फूड़, ई–कॉमर्स, चीन की चुनौती, पर्यावरण, पंचगव्य से स्वावलंबन, दैनिक जीवन में स्वदेशी, दीनदयाल जी उपाध्याय व दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का आर्थिक चिंतन पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संघठक श्री कश्मीरी लाल, राष्ट्रीय सहसंयोजक श्री सरोज मित्र व डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय विचार मंडल प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', उत्तर भारत के संघठक श्री सतीश कुमार, क्षेत्रीय संयोजक श्री कृष्ण कुमार शर्मा व दिल्ली–हरियाणा के संघठक श्री कमलजीत व श्री जितेन्द्र महाजन का मार्गदशन प्राप्त हुआ।

चार सत्रों की अध्यक्षता डॉ. सुषमा यादव (प्रोफेसर बाइसचांसलर, इग्नू विश्वविद्यालय), श्री शिवप्रकाश (प्रसिद्ध शिवनरेश उद्योग), श्री अनिल कुमार शर्मा (बैक्वंट हाल के मालिक) व श्री पंकज चौधरी (पतंजलि योग समिति) ने की। विशिष्ठ उपस्थिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री भारत भूषण जी, श्री दयानंद जी, श्री रवीन्द्र शर्मा व श्री भीमसैन सचदेवा के अतिरिक्त श्री विजय खुराना, डॉ. देवेन्द्र शर्मा, ए.सी.पी. श्री आनन्द मिश्रा सहित बड़ी संख्या में प्रोफेसर, एडवोकेटस आदि की रही। मंचीय गतिविधियों का संचालन श्री सुशील पांचाल ने किया। प्रांत संयोजक श्री गोविन्द राम अग्रवाल ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन किया। ❑❑

विचार वलय, इलाहाबाद

इलाहाबाद–स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक और पेसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रतिकुलपति प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार के नाम पर दुनिया के आम आदमी का शोषण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर प्रोसेस पेटेंट को भारत में फिर से लागू करने के लिए जनमत तैयार करने की आवश्यकता है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में स्वदेशी जागरण मंच महानगर की ओर से विचार वलय के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर आयोजित व्याख्यान में प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि आज भारत दुनियां में फर्मेसी आफ दि वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। फार्मा सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी दस फीसदी है। यदि अनिवार्य लाईसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तो देश में आम आदमी का ईलाज कराना न सिर्फ महंगा हो जाएगा, बल्कि फार्मा सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी दस से घटकर दो फीसदी रह जाएगी। उन्होंने कहा कि पेटेंट के मुद्दे पर अमेरिकी नीतियों का विरोध सोशल मीडिया के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विनिर्माण के क्षेत्र में चीन की हिस्सेदारी अमेरिका से भी अधिक 23 फीसदी के करीब है जबकि भारत दो फीसदी पर है।

उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कॉपी राईट के नाम पर विकसित देशों का शोषण कर रही हैं। कॉपी राईट की अवधि 15–20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा की जिस तरह से चीन ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर विंडो का इस्तेमाल सीमित किया, उसी तरह भारत को भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर राजस्व को बचाना चाहिए।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष करन सिंह पटेल,डा अवधेश झा, डा. मार्तंड सिंह, डा. प्रमोद शुक्ल, इन्द्रसेन सिंह तोमर, विमला व्यास,आदर्श त्रिपाठी, हरिओम नारायण पाण्डे, सर्वेश सिंह, भाष्कर तिवारी, अखिलेश श्रीवास्तव, डा. हेमंत पुण्डीर, अरविन्द सिंह आदि उपस्थित थे। ❑❑